mediaauditornews@gmail.com mediaauditor Epaperdainikmediaauditor.in mediaauditor वर्ष-29 अंक-91 पृष्ठ-8 मूल्य-3 रूपये

रीवा

04 अप्रैल 2025 शुक्रवार

दैनिक मीडियाऑडीटर

रीवा, सतना से एक साथ प्रकाशित

महिला हॉकी खिलाड़ी...

@ पेज 7

8 मार्च को जिन बच्चियों का हुआ जन्म, उनके नाम एफडी कराएगा मंदिर ट्रस्ट

नई दिल्ली (एजेंसी)। सिद्धिविनायक गणपति मंदिर ट्रस्ट ने 'श्री सिद्धिविनायक भाग्यलक्ष्मी योजना' शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाली

● सिद्धिविनायक गणपति मंदिर ट्रस्ट ने शुरू की योजना

बच्चियों के नाम पर उनकी माता के बैंक खाते में 10,000 रुपये की एफडी (स्र्वष्ठ) रखी जाएगी। ट्रस्ट की प्रबंधन समिति ने इस योजना को मंजूरी दी है और इसे सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा गया है। ट्रस्ट की ओर से इंडिया टीवी से बात करते हुए ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष

पवन त्रिपाठी ने बताया कि मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही इस योजना के नियम और शर्तें घोषित किए जाएंगे।

बता दें कि इस योजना को लेकर ट्रस्ट ने प्रस्ताव दिया है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन जन्म लेने वाली बच्चियों के लिए यह योजना लागू की जाए। श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक 31 मार्च को ट्रस्ट के अध्यक्ष सदानंद सरवणकर की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में 2024-25 के वार्षिक रिपोर्ट और 2025-26 के बजट पर विस्तार से चर्चा की गई। वर्ष 2024-25 के लिए ट्रस्ट की अनुमानित आय 114 करोड़ रुपये थी, लेकिन यह आय बढ़कर 133 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। ट्रस्ट ने अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 154 करोड़ रुपये के राजस्व का लक्ष्य तय किया है।

मंदिरों में वीआईपी कल्चर को लेकर भी बात करते हुए मंदिर के ट्रस्टी कमेटी के सदस्य राहुल लोंढे ने बताया कि मंदिर प्रांगण में सभी भक्त एक समान है और जिन्हें जरूरत होती है उन्हें मंदिर के कर्मचारी खुद ही ड्ढक्कलाइन से अंदर लेकर आते हैं। यही कारण है कि मंदिर ट्रस्ट को जहां वर्ष 2024-25 में वार्षिक आय 114 करोड़ होने की उम्मीद थी, वह बढ़कर 133 करोड़ हो गई और आने वाले साल में भी उम्मीद है कि ट्रस्ट की आय 154 करोड़ रुपए तक पहुंचेगी, जिसमें, श्रद्धालुओं द्वारा दिए जाने वाले दान, नारियल, लड्डू की बिक्री सभी सम्मिलित है। श्रद्धालुओं द्वारा किए जाने वाले दान का इसी प्रकार के सामाजिक कार्यों में उपयोग किया जाता है।

संक्षिप्त समाचार

यूनान के लेस्बोस द्वीप के निकट पलटी प्रवासियों से भरी नाव, 7 लोगों की मौत

एथेंस (एजेंसी)। यूनान में लेस्बोस द्वीप के पास प्रवासियों से भरी एक नौका के पलटने की जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि यह नौका तुर्की से प्रवासियों को एक निकटवर्ती यूनानी द्वीप पर ले जा रही थी। इसी दौरान हादसा हो गया। इस नाव के पलट जाने से कम से कम सात लोगों की मौत हो गई, जिनमें दो बच्चे भी शामिल हैं। यूनान के तटरक्षक बल ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

घटना की जानकारी मिलते ही लेस्बोस द्वीप के उत्तरी तट पर खोज और बचाव अभियान तत्काल प्रभाव से शुरू कर दिया गया। इसके दौरान मृतकों के शव बरामद किए गए। तटरक्षक बल ने बताया कि 23 लोगों को बचा लिया गया है। इसने बताया कि नाव पर सवार कुल लोगों की संख्या और उनकी राष्ट्रीयता के बारे में तत्काल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। तटरक्षक बल ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है।हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया है कि नौका में कुल कितने लोग सवार थे।

वैश्विक उथल-पुथल पर जयशंकर ने दुनिया को किया आगाह

बैंकाक (एजेंसी)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित जवाबी शुल्क के बीच, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बृहस्पतिवार को कहा कि दुनिया 'स्व-सहायता' के युग की ओर बढ़ रही है और हर क्षेत्र को खुद पर ध्यान देना होगा। जयशंकर ने बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (बिम्सटेक) के 20वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि छोटी आपूर्ति श्रृंखलाएं और निकट पड़ोसी अब पहले की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। उन्होंने कहा, ''वास्तविकता यह है कि दुनिया स्व-सहायता के युग की ओर बढ़ रही है। हर क्षेत्र को खुद पर ध्यान देने की जरूरत है, चाहे वह

खाद्य, ईंधन और उर्वरक आपूर्ति, टीके या त्वरित आपदा प्रतिक्रिया हो।'' विदेशमंत्री ने कहा, ''हम अपनी आंखों के सामने इसे घटित होते देख रहे हैं। समय वास्तव में बदल गया है। छोटी आपूर्ति श्रृंखलाएं और निकट पड़ोसी पहले की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं।'' जयशंकर जहां बिम्सटेक मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए यहां हैं। वहीं, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बृहस्पतिवार को यहां पहुंचे। मंत्री ने कहा कि बिम्सटेक शिखर सम्मेलन ''बहुत अनिश्चित और अस्थिर समय में हो रहा है जबकि वैश्विक व्यवस्था उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है।'' उन्होंने कहा, ''इससे हमें बिम्सटेक को और अधिक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रोत्साहित होना चाहिए। नई व्यवस्था, जिसकी रूपरेखा अब दिखाई देने लगी है, मूल रूप से अधिक क्षेत्रीय और एजेंडा-विशिष्ट है।'' मंत्री ने कहा, ''वह युग जब कुछ शक्तियां अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को अपने हाथ में लेती थीं, अब पीछे छूट चुका है।

दिल्ली में दूसरे राज्य की महिलाओं को मिलेगी मुफ्त बस सेवा?

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली सरकार की मुफ्त बस यात्रा योजना सिर्फ उन महिलाओं के लिए उपलब्ध होगी, जो राष्ट्रीय राजधानी में रहती हैं। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग दिल्ली की महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने के लिए 'स्मार्ट कार्ड' जारी करने की कवायद शुरू करने जा रहा है, जो 'आजीवन' वैध

रहेगा। अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड पाने की इच्छुक महिलाओं के लिए जल्द ही पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू करेगी। यह कदम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर गुलाबी टिकट योजना के तहत भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के कुछ दिनों बाद उठाया गया है। गुप्ता ने कहा था, ÷हम महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम महिलाओं के लिए डिजिटल यात्रा कार्ड शुरू करेंगे, जो उन्हें सरकारी बसों में कभी भी स्वतंत्र रूप से मुफ्त यात्रा करने की सुविधा देगा, जिससे टिकट से जुड़ा 'गुलाबी भ्रष्टाचार' खत्म हो जाएगा।÷ उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि दक्षता बढ़ाने के लिए टिकट प्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल किया जाएगा। गुप्ता ने कहा था कि संपूर्ण प्रणाली का आधुनिकीकरण किया जाएगा और पारदर्शिता एवं दक्षता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा त्रुटिपूर्ण योजनाओं में सुधार किया जाएगा।

सीएम रेखा गुप्ता ने किए कई बड़े ऐलान

'दिल्ली की सड़कों पर 2026 तक दौड़ेंगी 11000 बसें'

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज विधानसभा में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम और शमन पर कैग रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान राजधानी के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार दिल्ली को प्रदूषण-मुक्त और हरित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम ने बताया कि 2026 तक दिल्ली की सड़कों पर 11000 बसें दौड़ेंगी, जो सार्वजनिक परिवहन को मजबूत कर वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करेंगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 6484 बसें चल रही हैं, जबकि शहर को 11000 बसों की जरूरत है।

सीएम ने पिछले सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी नीतियों ने दिल्ली की हवा को जहरीला बनाया और संसाधनों का दुरुपयोग किया। उन्होंने कहा, 'पिछली सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को कमजोर किया, जिसके चलते दिल्ली बीमार होती गई। हमारी

सरकार पहले दिन से इस दिशा में काम कर रही है।' इसके तहत रूट रेशनलाइजेशन को ठीक कर हर कोने तक बसें पहुंचाई जाएंगी। साथ ही, इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग स्टेशनों का विस्तार होगा और 2026 तक 18000 सार्वजनिक व 30000 निजी चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए जाएंगे।

प्रदूषण नियंत्रण के लिए 1000 वॉटर स्प्रिंकलिंग मशीनें पूरे साल तैनात की जाएंगी। सीएम ने कहा, 'पिछली सरकार ने इसे सर्दियों तक सीमित रखा, जबकि प्रदूषण सालभर की समस्या है।' इसके अलावा, 6 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन और 500 ट्रैफिक कैमरे लगाए जाएंगे, जो प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर नजर रखेंगे। दिल्ली में प्रवेश करने वाले बाहरी वाहनों के लिए नई नीति लाई जाएगी, जिसमें प्रदूषण प्रमाणपत्र अनिवार्य होगा। वहीं, ई-वेस्ट के निपटान के लिए एक नया इको पार्क बनेगा, जबकि 70 लाख नए पौधे लगाकर हरित क्षेत्र बढ़ाया जाएगा।

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, 'पिछले पौधारोपण कागजों तक सीमित थे। हम स्कूलों और नागरिकों को जोड़कर इसे सफल बनाएंगे।'

साथ ही, एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित होगा, जो वायु गुणवत्ता और कचरे की निगरानी करेगा। पुराने वाहनों पर सख्ती और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन भी सरकार की प्राथमिकता है। रेखा गुप्ता ने कहा, 'हम घोषणाओं तक सीमित नहीं रहेंगे। दिल्ली को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए ठोस कदम उठाएंगे।'

महाराष्ट्र के सोलापुर में लगा भूकंप का झटका

सतना (एजेंसी)। , जानें कितनी रही तीव्रता भारत समेत दुनियाभर के विभिन्न देशों में भूकंप की घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। हाल ही में भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में भी विनाशकारी भूकंप आया जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई। भारत के अनेक राज्यों में भी बीते कुछ

समय से लगातार भूकंप की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब गुरुवार को महाराष्ट्र में भी भूकंप की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक, गुरुवार को महाराष्ट्र में सोलापुर जिले के कुछ हिस्सों में भूकंप के झटके लगे हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (ह्रष्टस्) की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, गुरुवार को महाराष्ट्र में सोलापुर में भूकंप के हल्के झटके महसूस हुए हैं। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 2.6 मापी गई है। सोलापुर जिले में भूकंप का झटका पूर्वाह्न 11 बजकर 22 मिनट पर दर्ज किया गया।

'भाजपा सरकार के हटने पर नया संशोधन लाएंगे'

वक्फ बिल को लेकर बोलीं सीएम ममता बनर्जी

मथुरा (एजेंसी)। केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया वक्फ संशोधन विधेयक गुरुवार को लोकसभा से पास हो गया है। इस बिल को लेकर बुधवार को पूरे दिन बहस चली और गुरुवार को आधी रात वोटिंग हुई। बिल के पक्ष में 288 और बिल के विपक्ष में 232 वोट पड़े। इसके साथ ही लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पास हो गया है। सत्ताधारी दल इस बिल को अल्पसंख्यकों के लिए लाभकारी बता रहा है तो वहीं, विपक्षी दल बिल की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। इन सब के बीच अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी भाजपा पर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने कहा है कि भाजपा ने देश को बांटने के लिए वक्फ (संशोधन) विधेयक पेश किया है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को संवाददाताओं से कहा- ''जब मौजूदा सरकार को हटाकर नई सरकार बनेगी तो हम भाजपा द्वारा लाए गए इस वक्फ विधेयक को निष्प्रभावी करने के लिए एक नया संशोधन लाएंगे। भाजपा देश को बांटने के लिए यह वक्फ विधेयक लाई है।''

इससे पहले सीएम ममता बनर्जी ने बुधवार को भी एक बयान में भाजपा पर विभाजनकारी एजेंडा लागू करने का आरोप लगाया था और पार्टी की आलोचना की थी।

ममता ने कहा था- ''मेरे सांसद वक्फ मुद्दे पर बोलने के लिए दिल्ली में मौजूद हैं। जुमला पार्टी का एक ही एजेंडा है - देश को बांटना। वे फूट डालो और राज करो में विश्वास करते हैं।''

सत्ताधारी एनडीए के नेताओं ने वक्फ संशोधन विधेयक का पुरजोर बचाव किया और इसे अल्पसंख्यकों के लिए लाभकारी बताया है। वहीं, विपक्षी दलों ने इस बिल की निंदा की है और वक्फ संशोधन विधेयक को मुस्लिम विरोधी करार दिया है।

वक्फ के पास इतनी संपत्ति, लेकिन पैसा जा कहां रहा

आरिफ मोहम्मद खान ने की टिप्पणी

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को पास कर दिया गया है। वहीं राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा की जा रही है। इसे लेकर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, ÷मैं कुछ समय तक उत्तर प्रदेश वक्फ मंत्रालय में रहा था। मैंने मुकदमेंबाजी के अलावा कुछ नहीं देखा है। 1980 में मुस्लिम महिला सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। इसमें कहा गया था कि अगर तलाकशुदा महिला की देखभाल करने वाले कोई नहीं है तो उसे वक्फ बोर्ड की तरफ से भत्ता दिया जाएगा। दो साल बाद मैंने संसद में पूछा कि वक्फ बोर्ड ने क्या प्रवधान किया है और तलाकशुदा महिला को भत्ते के रूप में कितने राशि दी जाती है।÷

उन्होंने कहा कि दो साल बाद, मुझे जवाब मिला कि किसी भी वक्फ बोर्ड ने एक पैसे का प्रावधान नहीं किया है। वक्फ बोर्ड की हालत यह है कि उसके पास इतनी संपत्ति है और उनके पास वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो यह

पैसा आखिर जा कहां रहा है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है और इसमें सुधार की जरूरत है। मुझे नहीं पता कि इसमें कोई बदलाव होने वाला है या नहीं, लेकिन बदलाव की जरूरत है। बता दें कि इस मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गुरुवार को बयान दिया है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड पर बृहस्पतिवार को सीधा हमला करते हुए इस पर भूमि अतिक्रमण करने का आरोप लगाया और इस बात पर जोर दिया कि सार्वजनिक और ऐतिहासिक स्थलों पर इसका मनमाना दावा ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहां श्रृंगवेरपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ''आप यहां निषादराज की पौराणिक भूमि पर कब्जा देख रहे हैं ना। शहर में जगह-जगह वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए हैं। यहां तक की कुंभ के समय भी बयान दिए गए कि कुंभ की भूमि भी वक्फ की है। हमने पूछा था- क्या वक्फ बोर्ड भू-माफिया बन गया है।''

स्टारलिंक को 'बार्गेनिंग चिप' की तरह इस्तेमाल करे सरकार

राज्यसभा में राघव चड्ढा ने कहा

नई दिल्ली (एजेंसी)। राज्यसभा में गुरुवार को एक महत्वपूर्ण चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने भारत सरकार को सलाह दी है कि वह अमेरिका के साथ टैरिफ को लेकर बातचीत में स्टारलिंक को %बार्गेनिंग चिप% की तरह इस्तेमाल करे। उन्होंने साथ ही स्टारलिंक को लेकर कुछ चिंताजनक घटनाओं का भी हवाला दिया। बता दें कि भारत सरकार फिलहाल स्टारलिंक की भारत में एंट्री को लेकर सतर्क है और वह किसी भी तरह की मंजूरी देने से पहले सुरक्षा से जुड़े हर पहलू को जांच-परख रही है।

अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ से निपटने के लिए राघव चड्ढा ने सरकार को सुझाव दिया कि एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को दी जाने वाली मंजूरी रोकी जानी चाहिए और उसका इस्तेमाल अमेरिका से फिर से टैरिफ को लेकर

बातचीत में %बर्गेनिंग चिप% के तौर पर करना चाहिए। उन्होंने साथ ही कुछ चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि कुछ महीने पहले अंडमान में 6000 किलो सिंथेटिक ड्रग्स की जब्ती के दौरान यह पाया गया कि म्यांमार के ड्रग तस्करों ने नेविगेशन के लिए स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट का इस्तेमाल किया था।

जेलेंस्की के बयान का भी दिया हवाला

चड्ढा ने साथ ही कहा कि यूक्रेन युद्ध के दौरान एलन मस्क ने खुद सोशल मीडिया पर कहा था कि %स्टारलिंक यूक्रेनियन आर्मी की रीढ़ है, अगर मैं इसे बंद कर दूं तो पूरी फ्रंटलाइन धराशायी हो जाएगी।% उन्होंने कहा कि भारत को भी इससे सतर्क रहना चाहिए क्योंकि देश की संप्रभुता और सुरक्षा सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि वह हर उस मुद्दे को सदन में उठाते रहेंगे, जो भारतीय हितों और भारत की आर्थिक संप्रभुता को प्रभावित करता है। उन्होंने साफ किया कि उनकी बातें किसी कंपनी के खिलाफ नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और डेटा नीति की मजबूती के लिए है। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने से पहले कड़े सुरक्षा मानकों और नियामक शर्तों का पालन करना होगा। सरकार ने स्टारलिंक से भारत में एक कंट्रोल सेंटर स्थापित करने की शर्त रखी है, ताकि आपात स्थिति में संचार सेवाओं पर सरकार का नियंत्रण रहे और कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके। साथ ही सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि स्टारलिंक को भारत में ही अपना डेटा स्टोर करना होगा और सरकार के पास जरूरत पड़ने पर सैटेलाइट इंटरनेट डेटा की जांच करने का अधिकार होगा।

बदमाशों ने आंख में मिर्ची फेंक कर लूट लिए लाखों रुपये

पालघर (एजेंसी)। महाराष्ट्र के पालघर जिले में पुलिस को शादी के निमंत्रण कार्ड से लूटपाट का एक मामला सुलझाने में मदद मिली है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को बताया कि लूटपाट की घटना 28 मार्च को जौहर के वावर गांव के पास हुई थी। जिला पुलिस अधीक्षक बालासाहेब पाटिल ने बताया कि बोरु खांडू बिन्नर (30) मोखाडा तालुका के खोडाला का निवासी है और वह एक पिकअप वैन

में यात्रा कर रहा था, तभी तीन अज्ञात व्यक्तियों ने अपनी मोटरसाइकिल खराब होने का बहाना करके उसे रोका। पाटिल के मुताबिक, बिन्नर ने वैन चालक से उनकी मदद के लिए रुकने को कहा, जिसके बाद तीनों ने उनकी आंखों में मिर्च पाउडर फेंका और चालक की सीट के पीछे रखे 6,85,500 रुपये नकद लूटकर भाग गए। भागने से पहले उन्होंने व्यक्ति को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी।

वन विभाग ने 1600 करोड़ से अधिक राजस्व प्राप्त कर नया कीर्तिमान स्थापित किया

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। वन विभाग की कुशल नीति, वन उत्पादों के प्रबंधन, डिजिटल प्रणाली और पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप राजस्व में वृद्धि हो रही है। वन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1600 करोड़ से अधिक राजस्व प्राप्त कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यह वन विभाग की अब तक की सबसे अधिक राजस्व प्राप्ति है, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में 200 करोड़ रुपये से अधिक है। वन विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 में 1425 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया, वर्ष 2022-23 में 1400 करोड़ और वर्ष 2021-22 में 1444 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था।

वन विभाग को प्राप्त राजस्व में सबसे बड़ा योगदान टिम्बर की बिक्री से हुआ है। इस वर्ष विभाग द्वारा टिम्बर बिक्री से 850 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। वन विभाग की नीलामी प्रक्रिया और बढ़ती मांग के कारण टिम्बर की बिक्री में वृद्धि हुई है। इसके अलावा अन्य वानिकी उत्पादों और पर्यावरण से जुड़े शुल्क से भी आय में वृद्धि हुई। वन विभाग को राजस्व संग्रहण की प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल बनाने से राजस्व में वृद्धि हुई है। ऑनलाइन चालान से विभाग को 1528 करोड़ की आय हुई, जबकि ट्रांसफर चालान से 763 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है।

गेहूँ उपार्जन के लिये किसान अब 9 अप्रैल तक करा सकते हैं पंजीयन-मंत्री श्री राजपूत

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि किसानों के हित में रबी विपणन वर्ष 2025-26 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिये पंजीयन की अवधि 9 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। पूर्व में पंजीयन की अवधि 31 मार्च 2025 तक निर्धारित की गई थी। मंत्री श्री राजपूत ने किसानों से आग्रह किया है कि जिन किसानों ने अभी तक पंजीयन नहीं करवाया है, वे 9 अप्रैल तक गेहूँ उपार्जन के लिये पंजीयन जरूर करायें। गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रूपये है और राज्य सरकार द्वारा 175 रूपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जा रहा है। इस तरह से गेहूँ की खरीदी 2600 रूपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है। उल्लेखनीय है कि गेहूँ उपार्जन के लिये 31 मार्च तक 15 लाख 9 हजार 324 किसान पंजीयन करा चुके हैं। गेहूँ का उपार्जन भी जारी है।

एम.पी. ट्रांसको के ट्रांसमिशन लाइन मेंटेनेन्स कर्मियों के लिये आयोजित होंगे फ्री हेल्थ चेक-अप कैम्प

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी (एम.पी. ट्रांसको) के मध्यप्रदेश में कार्यरत सभी एम.पी. ट्रांसको के सभी ट्रांसमिशन लाइन मेंटेनेन्स कार्यों में संलग्न सभी स्थायी, संविदा एवं आउटसोर्स कर्मियों के लिये फ्री हेल्थ चेक-अप कैम्प आयोजित किये जायें। साथ ही ट्रांसमिशन लाइन मेंटेनेन्स के सभी उप संभागों में जीवन रक्षक तकनीक पर कार्यशाला आयोजित की जायें। मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध संचालक ने यह निर्देश जबलपुर में आयोजित ट्रांसमिशन लाइन मेंटेनेन्स कार्मिकों के लिये आयोजित 02 दिवसीय कार्यशाला में दिये। उन्होंने कहा कि कंपनी के सभी कार्मिक आउटसोर्स कर्मियों का विशेष ध्यान रखें और उन्हें वह सब सुविधाएं उपलब्ध करावें जिससे उनका हित हो सके। प्रबंध संचालक ने कार्य के दौरान दुर्घटनाओं को रोकने के लिये मेंटेनेन्स कर्मियों के मोबाइल इस्तेमाल पर रोक का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये।

प्रदेश सरकार किसानों की सरकार है - मंत्री उइके

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। प्रदेश सरकार किसानों की सरकार है। किसानों के हितार्थ कई योजनाएं संचालित कर उन्हें लाभ प्रदान किया जा रहा है। वहीं, उनकी खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। यह बात लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं सिंगरौली जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके ने संयुक्त तहसील दुधमनिया में 8 करोड़ की लागत से निर्मित भवन के लोकार्पण अवसर पर कही। इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह भी उपस्थित थीं।

मंत्री श्रीमती उइके ने कहा कि इस संयुक्त भवन के निर्माण से अब 65 गांवों के लोगों को लाभ प्राप्त होगा। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों एवं आम नागरिकों की समस्याओं के निराकरण के लिये साइबर तहसील, लोक सेवा गारंटी लागू कर त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जहां गरीबों के लिए आवास स्वीकृत किए जा रहे हैं ,वहीं किसानों के लिए सम्मान निधि प्रदान की जा रही है।

मंत्री श्रीमती उइके ने कहा कि महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने के लिए 'लाड़ली बहना योजना' चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से आर्थिक सहायता देकर महिलाओं का

सशक्तिकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में क्षेत्र के विकास के लिए कॉलेज एवं अस्पताल खोले जाएंगे। सरकार प्रवेश उत्सव के माध्यम से बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए निरंतर कार्य कर रही है। 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक 'स्कूल चले हम' अभियान चलाया जा रहा है। हमें बेटा-बेटी के बीच का अंतर समाप्त करना है और बेटियों को भी बेटों की तरह शिक्षा का अधिकार देना है। कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी अपने बच्चों का विद्यालय में प्रवेश दिलाएं।

राज्यमंत्री श्रीमती राधा सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए सतत प्रयासरत है। विकास के कई कार्य संचालित होंगे। साथ ही, किसानों एवं नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए कई योजनाएं और सुविधाएं दी जा रही हैं। आने वाले समय में दुधमनिया में भी महाविद्यालय प्रारंभ कराने का प्रयास किया जाएगा।

इस अवसर पर विधायक सिंगरौली राम निवास शाह, विधायक देवसर राजेंद्र मेश्राम, विधायक धौहनी कुवर सिंह टेकाम, विधायक सिहावल विश्वामित्र पाठक, महापौर श्रीमती रानी अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष सोनम सिंह, प्राधिकरण अध्यक्ष दिलीप शाह, नगर निगम अध्यक्ष देवेश पांडेय, श्री सुंदरलाल शाह, जिला पंचायत उपाध्यक्ष अर्चना सिंह, पूर्व विधायक अमर सिंह, जनपद पंचायत अध्यक्ष सिया दुलारी सहित वरिष्ठ समाजसेवी एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिये हुई समेकित राज्य स्तरीय बैठक

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। प्रमुख सचिव पर्यावरण डॉ. नवनीत मोहन कोठारी की अध्यक्षता में पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिये भोपाल में समेकित राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय बैठक हुई। बैठक में किसान कल्याण तथा कृषि विकास, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, उद्योग, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, राजस्व, उद्यानिकी विभाग और मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में धान एवं गेहूँ की कटाई के बाद जलने वाली पराली से होने वाले वायु प्रदूषण एवं उनसे पड़ने वाले स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव की रोकथाम के लिये प्रभावी कार्रवाई करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। प्रमुख सचिव डॉ. कोठारी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पराली जलाने की घटनाओं को रोकने तथा वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाये जा रहे हैं। प्रमुख सचिव डॉ. कोठारी ने कहा कि कृषि विभाग द्वारा गेहूँ की फसल की कटाई में उपयोग होने वाली मशीनों में रिपर/बेलर लगाना अनिवार्य किया जाये। उन्होंने कहा कि पराली के वैकल्पिक उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिये प्रदेश में स्थापित ताप विद्युत गृहों के अधिकारियों के साथ बैठक कर कृषि अवशेषों का दहन करने की कार्रवाई की जाये। उन्होंने कहा कि विगत वर्षों में कितनी मात्रा में कृषि अवशेषों का निष्पादन किया गया है तथा इस वर्ष की कार्य-योजना बनायी जाये। प्रमुख सचिव डॉ. कोठारी ने कहा कि सभी संबंधित विभाग व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से प्रदेश के किसानों को पराली जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में अवगत कराएं। उन्होंने पराली जलाने के स्थान पर उपलब्ध विकल्प और शासन द्वारा दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि की जानकारी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया और स्थानीय केबल नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराये जाने के निर्देश भी दिये।

सदस्य सचिव मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया कि बोर्ड द्वारा एनएएसएएफआईआरएमएस पोर्टल पर सेटेलाइट से आग लगने की घटनाओं पर उपलब्ध जानकारी के माध्यम से प्रदेश के प्रमुख जिलों में आग लगने की घटनाओं की संख्या एवं उनके भौगोलिक निर्देशांक की जानकारी तैयार की गयी है।

मंत्री श्री चौहान ने बनासकांठा पहुंच कर घायल श्रमिकों का हाल जाना, बंधाया ढांढस

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री श्री नागर सिंह चौहान ने अधिकारी-कर्मचारियों के साथ देर रात गुजरात के बनासकांठा पहुंचकर मध्यप्रदेश के घायल श्रमिकों एवं उनके परिजन से मुलाकात कर हाल-चाल जाना। मंत्री श्री चौहान ने घायल श्रमिकों के परिजन से बात कर उन्हें ढांढस बंधाया। साथ ही राज्य सरकार के द्वारा घायल मजदूरों के उचित इलाज और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन भी दिया। मंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर गुजरात, बनासकांठा में घटना स्थल पर पहुंचकर स्थानीय प्रशासन से जानकारी प्राप्त की।

बनासकांठा जिले के डीसा अस्पताल पहुंचकर घायल श्रमिकों के इलाज के लिये उचित प्रबंध के निर्देश दिए। साथ ही घटना के दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश भी दिए। मंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्थानीय प्रशासन दोषियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी करेगा। मंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हादसे में मृतक एवं घायल श्रमिकों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मध्यप्रदेश सरकार ने पटाखा फैक्ट्री हादसे में घायल मृतकों के परिजनों को रुपये 2-2 लाख तथा घायल श्रमिकों को 50-50 हजार रूपये और गुजरात सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये एवं घायल श्रमिकों को 50-50 हजार रुपये आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।

प्रदेश में हाई एवं हायर सेकण्डरी स्कूलों में करियर काउंसलिंग की सुविधा

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। प्रदेश में शासकीय हाई एवं हायर सेकण्डरी स्कूलों में कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों के लिये करियर काउंसलिंग एवं गाइडेंस कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। उचित चयन श्रेष्ठ करियर कार्यक्रम में कक्षा 9वीं एवं 11वीं में जो विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं हो पाये हैं। उनके अभिभावकों को विद्यालय बुलाकर उसी कक्षा में प्रवेश के लिये काउंसलिंग की जा रही है। ऐसे विद्यार्थी जो आगे की पढ़ाई निरंतर नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें हार के आगे जीत कार्यक्रम में आईटीआई पाठ्यक्रम, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की जानकारी देकर उन्हें व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने के प्रयास किये जा रहे हैं। इस कार्य के लिये स्कूल शिक्षा विभाग ने समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर और करियर काउंसलर की सेवा लेने के लिये कहा गया है। इस योजना में आवेदकों को अपनी ग्राम पंचायत ग्राम रोजगार सेवक के साथ दाखिला लेने की आवश्यकता है। आवेदक को ट्रेनिंग सेंटर के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके लिये आवेदक को आवश्यक पहचान-पत्र, इनमें मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड एवं अन्य जानकारी रोजगार सेवक को देनी होगी। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षण के बाद ऋण उपलब्ध कराने में आवेदक को पूरी मदद दी जायेगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में देशभर में एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई है। इस योजना में 3 माह, 6 माह और एक साल के लिये युवाओं का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। कौशल संबंधी कोर्स पूरा करने के बाद सर्टिफिकेट दिये जाने का प्रावधान है।

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में धार्मिक यात्रा पर एनजीटी सत, रिपोर्ट मांगी

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में हर साल धार्मिक यात्रा होती है। इस पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सख्त रुख अपनाया है। पर्यावरण कार्यकर्ता अजय शंकर दुबे की याचिका पर सुनवाई हुई। एनजीटी ने पूछा कि 2022 में तत्कालीन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एपीसीसीएफ) शुभरंजन सेन ने इस यात्रा को प्रतिबंधित करने की सिफारिश की थी। लेकिन 2024 में पीसीसीएफ बनने के बाद उन्होंने खुद इसकी अनुमति क्यों दी? कोर जोन में सात दिन तक हजारों श्रद्धालु रुकते हैं। वे खाना बनाते हैं और कचरा फैलाते हैं। इससे जंगल की पारिस्थितिकी को खतरा हो रहा है। कानून के अनुसार, कोर एरिया में किसी भी मानवीय गतिविधि पर प्रतिबंध है। फिर भी हर साल सद्गुरु कबीर धर्मदास साहब वंशावली की यात्रा होती है। राज्य सरकार के अधिवक्ता प्रशांत एम. हरने ने बताया कि वन्यजीव संस्थान से विशेषज्ञ रिपोर्ट मंगाई जा रही है। एनजीटी ने राज्य सरकार से तीन हफ्तों में एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। अगली सुनवाई 8 जुलाई 2025 को होगी।

मुख्य सचिव ने की मंत्रालय में समस्त विभागों की समीक्षा

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने बुधवार को मंत्रालय में, वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभागीय योजनाओं की लक्ष्य पूर्ति की समीक्षा एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 के लक्ष्य निर्धारण को लेकर सभी विभागों की समीक्षा की। मुख्य सचिव श्री जैन ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में सभी विभागों की विभागीय योजनाओं की लक्ष्य पूर्ति की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक क्रियान्वयन समयपूर्वक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव श्री जैन ने बैठक में विजन ञ2047 के अंतर्गत विभागीय कार्य योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा

की। शासन के महत्वाकांक्षी गरीब, अन्नदाता, युवा एवं नारी मिशन के क्रियान्वयन से संबंधित कार्य योजना पर भी व्यापक चर्चा हुई। मुख्य सचिव श्री जैन ने संकल्प पत्र में सभी विभागों से जुड़े समस्त संबंधित बिंदुओं पर चर्चा कर, उनके पालन की स्थिति की भी समीक्षा की।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के प्राथमिकता वालें विषयों के क्रियान्वयन समय-सीमा में सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए, केन्द्र सरकार को भेजे जाने वाले उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं मांग स्थिति की भी जानकारी ली।

जनशिकायत निवारण, अंतर्विभागीय एवं विधानसभा से जुड़े विभिन्न विषयों पर बिंदुवार चर्चा हुई। मुख्य सचिव श्री जैन ने लंबित सीएस मॉनिट, भारत सरकार से प्राप्त अर्द्धशासकीय पत्रों की समीक्षा, पेपर कटिंग, सीएम हेल्पलाईन, ई-ऑफिस, सीपी ग्राम, विधानसभा प्रश्न एवं आश्वासन सहित कैग रिपोर्ट से संबंधित विभागीय बिंदुओं पर व्यापक चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित अंतर्विभागीय समितियों की बैठक की स्थिति की जानकारी लेकर आवश्यक क्रियान्वयन के लिए भी निर्देशित किया।

दीदी कैफे से ग्रामीण महिलाओं की आय में वृद्धि के साथ बढ़ रही है सामाजिक प्रतिष्ठा: मंत्री पटेल

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का सपना स्व-सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आत्म-निर्भर एवं स्वावलंबी बनाना है।

उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संचालित आजीविका स्वाद संगम (दीदी कैफे) ग्रामीण महिलाओं की आय में वृद्धि करने का साधन बन रहे हैं। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि स्व-सहायता समूह न केवल ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति को बेहतर कर रहे हैं बल्कि उनकी सामाजिक

प्रतिष्ठा को भी बढ़ा रहे हैं। मंत्री श्री पटेल ने बुधवार को विकास भवन एवं भोपाल हाट बाजार ने समूहों द्वारा संचालित आजीविका स्वाद संगम (दीदी कैफे) का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्रीमती दीपाली रस्तोगी, सीईओ एसआरएलएम श्रीमती हर्षिका सिंह, सीईओ आरआरडीए श्री दीपक आर्य, आयुक्त मनरेगा श्री अवि प्रसाद सहित अधिकारी-कर्मचारी और स्व-सहायता समूहों की महिलाएं उपस्थित रही। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि शास्त्रों एवं परंपरागत ज्ञान में उल्लेख है कि भोजन में स्वाद भोजन सामग्री के साथ ही बनाने वाले के भाव का भी होता है। दीदी कैफे में भोजन स्वादिष्ट है क्योंकि इसे तैयार करने वाली महिलाओं का अपनापन इसमें शामिल है। उन्होंने भोपाल हाट बाजार में मिलेट से तैयार व्यंजनो के लिए कैफे स्थापित करने की पहल की सराहना की। उन्होंने दोनों कैफे का अवलोकन कर व्यवस्थाएं देखी। उन्होंने समूह की महिलाओं से संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया। मंत्री श्री पटेल ने कैफे में सफाई व्यवस्था एवं कचरा प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

पोषण भी, पढ़ाई भी-आंगनवाड़ी केंद्रों में समग्र विकास की नई दिशा

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। बाल्यावस्था केवल खेल-कूद और मस्ती का समय नहीं है, बल्कि यह जीवन की आधारशिला रखने वाला महत्वपूर्ण दौर भी है। गर्भधारण से लेकर छह वर्ष की आयु तक का समय बच्चे के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए बेहद अहम होता है। विशेष रूप से पहले 1000 दिन, गर्भ के नौ महीने और जन्म के बाद के दो साल, बच्चे के भविष्य की नींव मजबूत करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस दौरान सही पोषण के साथ-साथ संज्ञानात्मक विकास के अवसर भी उतने ही आवश्यक होते हैं।

संयुक्त परिवारों की घटती संख्या और बदलते सामाजिक परिवेश के कारण अब घर में बच्चों को पारंपरिक रूप से मिलने वाला सहज शिक्षण प्रभावित हो रहा है। इसी कमी को पूरा करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को सशक्त बनाया जा रहा है, जहां गर्भवती महिलाओं, शिशुवती माताओं और छह वर्ष तक के बच्चों को पोषण आहार के साथ-साथ प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का मानना है कि बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिये न सिर्फ माता-पिता की बल्कि समाज की भागीदारी भी आवश्यक है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सक्षम आंगनवाड़ी की पोषण भी, पढ़ाई भी अभियान की शुरूआत 10 मई 2023 को की गई थी। इसका उद्देश्य प्रारंभिक बाल्यवस्था में देखभाल और शिक्षा पर आंगनवाड़ी प्रणाली का ध्यान केन्द्रित करना है। साथ ही आंगनवाड़ी केन्द्र को उच्च गुणवत्ता वाली बुनियादी सुविधाओं खेल के उपकरण और विधिवत प्रशिक्षित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ एक शिक्षण केन्द्र में परिवर्तित करना भी इसका उद्देश्य है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मानते है कि अच्छा पोषण न केवल शारीरिक वृद्धि बल्कि मानसिक विकास और सीखने की क्षमता को भी बढ़ावा देता है।

सतपुड़ा भवन में क्लर्क को सस्पेंड करने से पूरा दफ्तर नाराज, प्रदर्शन

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। राजधानी एक बड़ी सरकारी इमारत सतपुड़ा भवन में बुधवार का दिन हंगामा भरा रहा। सुबह दफ्तर खुलने के कुछ देर बाद ही बिल्डिंग के दूसरे माले पर आदिम जाति कल्याण विभाग के कर्मचारी एकसुर में नारेबाजी करते हुए अपने अपने कमरों से निकल गए। एकजुट होकर ये सभी कर्मचारी बाहर धरना देकर बैठ गए। दरअसल ये सभी कर्मचारी अपने साथी क्लर्क हर्षपाल को सस्पेंड करने से गुस्साए थे। कर्मचारियों का हंगामा देखकर भारी पुलिस बल बुला लिया गया था। जिला पुलिस बल के अलावा विशेष सशस्त्र बल, खुफिया पुलिस समेत सदी वर्दी में भी कई पुलिस कर्मी तैनात नजर आए। मंत्रालय के सुरक्षा अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए थे। प्रदर्शनकारी कर्मचारी आयुक्त श्रीमन शुक्ला के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे थे। कर्मचारियों का गुस्सा और नारेबाजी देख आखिरकार अफसरों को समझौता बैठक बुलानी पड़ी। कर्मचारियों ने यह मांग भी रख दी थी कि यदि निलंबन समाप्त नहीं किया तो आंदोलन करेंगे।

जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत बेला में लगाई गई जल चौपाल

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। *जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देशानुसार कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस के मार्गदर्शन में अमरपाटन विकासखंड की नवाकुर संस्था अस्तित्व पब्लिक वेलफेयर सोसायटी बेला एवं ग्राम विकास प्रस्पुट्टन समिति के द्वारा 2 अप्रैल 2025 को जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जल चौपाल आयोजित हुआ। जिला समन्वयक डॉ. राजेश तिवारी ने उपस्थित ग्रामीणजन और प्रस्पुट्टन समिति के सदस्यों के समक्ष जल के महत्व पर चर्चा करते हुए बताया कि जल संपूर्ण जीवों की मुख्य आवश्यकता है और अगर ये समाप्त हो गया तो गांव में खेती होना बंद हो जाएगी, पशु जीवित नहीं रहेंगे, पेड़ पौधे सूख जायेंगे। ऐसे भयावह परिस्थिति में मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। अत: समय रहते हमें अपने ग्राम के जल स्त्रोतों के संरक्षण की नितांत आवश्यकता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा जन-जन को जागृत करने और जल स्त्रोतों के संरक्षण के लिए 30 मार्च से 30 जून तक यह अभियान प्रारंभ किया गया है। हम सभी आज इस जल चौपाल के माध्यम से शपथ ले की हम पानी की बूंद बूंद बचाकर अपने गांव को पानीदार बनाए रखेंगे। अपने गांव के जल स्त्रोतों को संरक्षित रखते हुए निरंतर उसकी सफाई और सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। जल चौपाल के बाद सभी उपस्थित जन समूह द्वारा वृक्षारोपण की गतिविधि आयोजित की गई। कार्यक्र म में उपस्थित विकासखंड समन्वयक विश्वनाथ रैदास द्वारा पानी बचाने की विभिन्न तकनीकों की जानकारी साझा करते हुए बताया कि हम अपने गांव के पानी को गांव में ही रोकने का जतन करें जिससे सतही जल स्तर को बढ़ाया जा सके। कार्यक्र म में उपस्थित महिला कला दल द्वारा जल संरक्षण पर आधारित सामूहिक गीत के माध्यम से उपस्थित लोगों को जल बचाने की सीख दी। कार्यक्र म के अंत में सभी उपस्थित जन समूह द्वारा तालाब के किनारे गंगा आरती के माध्यम से जल की पूजा-अर्चना कर उसे संरक्षित करने की सामूहिक शपथ ली गई।*

प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग से गेंहू की फसल में आई कम लागत

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। प्राकृतिक खेती से रासायनिक उर्वरकों पर किसानों की निर्भरता कम हुई है उन्हें गेंहू की फसल में कम लागत में अधिक मुनाफा प्राप्त हुआ है। जिले के सिरमौर तहसील अन्तर्गत माड़ौ गांव के कृषक केदार प्रसाद कुशवाहा परंपरागत खेती छोड़कर प्राकृतिक खेती करने लगे। वह बताते हैं कि परंपरागत खेती में रासायनिक उर्वरकों, खरपतवार नाशक, कीटनाशक का उपयोग मंहगा पड़ता था साथ ही जमीन की उर्वराशक्ति भी कम हो रही थी। क ृ ष क केदार प्रसाद ने वर्ष 2023-24 से प्राकृतिक खेती की शुरूआत की। पूसा प्रजाति का गेंहू 3386 किस्म के उपचारित बीज प्राप्त कर सीडर से बुवाई की। आवश्यकतानुसार 20 से 21 दिनों में सिंचाई की गई। निदाई-गुड़ाई के उपरांत जीवामृत घोल का छिड़काव किया गया। सुपर सीडर से बुवाई का यह फायदा मिला कि फसल का अवशेष खाद के रूप में मिट्टी में मिल गया तथा पानी की बचत हुई और पराली नहीं जलाई गई जिससे प्रदूषण भी नहीं हुआ। केदार प्रसाद कहते हैं कि गेंहू की फसल अन्य फसलों की तुलना में कम खाद फसल है। यह फसल विधिधीकरण के लिये भी उपयुक्त है। इस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर केदार प्रसाद ने कम लागत में अधिक मुनाफा कमाया वह किसानों से इस पद्धति को अपनाने के लिये भी समझाइश दे रहे हैं। कृषक का मो. नं. 9229958796 है।

एम पी पब्लिक हायर सेकंडरी स्कूल त्योंथर में छात्राओं ने किया टॉप

मीडिया ऑडीटर,त्योंथर (निप्र)। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा आयोजित पांचवीं और आठवीं कक्षा का परीक्षा परिणाम विगत दिन जारी हो गया है जिसमें एमपी पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल त्योंथर की पांचवीं की छात्रा पुष्पांजलि सिंह ने 94 प्रतिशत के साथ विद्यालय में प्रथम स्थान हर्ष मिश्रा ने 93 प्रतिशत के साथ द्वितीय स्थान और मान्या गुप्ता ने 92 प्रतिशत अंक के साथ तृतीय स्थान प्राप्त किया वही कक्षा आठवी में छात्रा ज्योति पांडे ने 92 प्रतिशत के साथ विद्यालय में प्रथम स्थान,शिवम सिंह ने 90 प्रतिशत अंक के साथ द्वितीय स्थान और जाह्नवी ठाकुर ने 90 प्रतिशत अंक के तृतीय स्थान प्राप्त किया वही विद्यालय अध्ययन रत समस्त छात्रों का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा बच्चों की इस

उपलब्धि पर संचालक अभय नाथ श्रीवास्तव , प्रिंसपल बीजू एस,अजय श्रीवास्तव, बीजू एस ,लवलेश द्विवेदी,सिवानी तिवारी, रोजी खान ,सरिता सिंह सहित समस्त विद्यालय परिवार ने प्रसन्नता व्यक्त की और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

समाधान ऑनलाइन के एजेण्डा बिन्दुओं के सभी प्रकरण तीन दिवस में निराकृत करें - कलेक्टर

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने टीएल पत्रों तथा सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी समाधान ऑनलाइन में शामिल 10 एजेण्डा बिन्दुओं में लंबित सीएम हेल्पलाइन की सभी शिकायतों का तीन दिवस में अनिवार्य रूप से निराकरण करें। साथ ही मार्च माह में दर्ज शिकायतों एवं 50 दिन से अधिक शिकायतों भी सात दिवस में शत-प्रतिशत निराकरण कराएं। व्यक्तिगत रूचित लेकर स्वयं शिकायतें देखें तथा आवेदकों से बात करें। लंबित प्रकरणों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण करें। शिकायतों पर तथ्यों सहित प्रतिवेदन दर्ज करें। कार्यपालन यंत्री पीएचई पेयजल से जुड़ी सीएम हेल्पलाइन की सभी शिकायतों का तत्काल निराकरण करें। खराब हैण्डपंपों के सुधार का अभियान चलाएं। पंचायतों के सहयोग से नलजल योजनाओं का भी नियमित संचालन कराएं। जिन क्षेत्रों में जल स्तर में तेजी से गिरावट हो रही है वहाँ हैण्डपंपों में सिंगल फेज के मोटर लगाकर पेयजल की आपूर्ति कराएं। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज तीन हजार से अधिक शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित करें। सभी एसडीएम हैण्डपंपों में अवैध कब्जे की सभी शिकायतों का दो दिवस में निराकरण करें।

कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग, खाद्य विभाग, नगरीय निकाय, स्वास्थ्य विभाग, श्रम विभाग तथा ऊर्जा विभाग में भी बड़ी संख्या में आवेदन पत्र लंबित हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जननी सुरक्षा योजना और प्रसूति सहायता के सभी प्रकरणों में तीन दिवस में भुगतान कराकर संतुष्टिपूर्वक शिकायत निराकरण करें। अधीक्षण यंत्री ऊर्जा बिजली की आपूर्ति, ट्रांसफार्मर बदलने तथा बिजली बिलों में सुधार के सभी प्रकरण तीन दिवस में निराकृत कराएं। उपार्जन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि सभी खरीदी केन्द्रों में बारदाने उपलब्ध करा दिए गए हैं। स्लॉट बुक करके खरीदी शुरू करें। किसानों के पंजीयन की तिथि भी 9 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। शेष बचे किसानों का पंजीयन कराएं। सभी राजस्व अधिकारी खरीदी केन्द्रों का निरीक्षण करके खरीदी केन्द्र में किसानों के लिए छाया-पानी की सुविधा, गेंहू के भण्डारण, तौल-कांटे, हम्माल तथा अन्य सुविधाएं सुनिश्चित करें। खाद्य सुरक्षा योजना के हितग्राहियों की शेष बची ई केवाईसी 15 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से कराएं। सभी सहायक आपूर्ति अधिकारी उचित मूल्य दुकानों में ई केवाईसी की प्रगति की प्रतिदिन रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जिला आपूर्ति अधिकारी लापरवाह सेल्समैनों को पद से पृथक करने की कार्यवाही करें। एसडीएम खाद्यान्न वितरण और ई केवाईसी की नियमित समीक्षा करें। कलेक्टर ने कहा कि जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्राम रोजगार सहायकों तथा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से हितग्राहियों की समग्र आईडी अपडेट कराएं। इसके लिए प्रत्येक अपडेशन में 14 रुपए की राशि दी जा रही है। प्रत्येक पंचायत में शिविर लगाकर 30 अप्रैल तक समग्र ई केवाईसी अपडेट कराएं।

बैठक में कलेक्टर ने कहा कि ई आफिस योजना के तहत अभी केवल 23 कार्यालय ऑनबोर्ड हुए हैं। शेष 33 विभागों के कार्यालय प्रमुख संचालनालय स्तर से ई मेल आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करके दो दिन में जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को उपलब्ध करा दें। सभी विभागों के ऑनबोर्ड होने के बाद ई आफिस पोर्टल के माध्यम से ही फाइलों का संचालन और निराकरण होगा। बैठक में कलेक्टर ने न्यायालय में दर्ज प्रकरणों में जवाब दावा तथा अवमानना प्रकरणों में न्यायालय के निर्देशों का पालन करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जिन कार्यालयों में अवमानना के 10 से अधिक प्रकरण लंबित हैं उनके कार्यालय प्रमुखों की वेतनवृद्धि अवरूद्ध की जाएगी। बैठक में आयुक्त नगर निगम डॉ सौरभ सोनवड़े, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर, अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी, संयुक्त कलेक्टर पीके पाण्डेय, संयुक्त कलेक्टर श्रेयस गोखले, सभी एसडीएम, जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

मऊगंज जिले में पंजीकृत चिकित्सक के नवीन प्रिस्क्रिप्शन के बिना कोरेक्स का विक्रय प्रतिबंधित

कलेक्टर ने जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर संजय कुमार जैन ने मऊगंज जिले में पंजीकृत चिकित्सक के नवीन प्रिस्क्रिप्शन के बिना कोरेक्स कफ सिरप का विक्रय प्रतिबंधित कर दिया है। उन्होंने धारा 163 के तहत संपूर्ण जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं जो तत्काल प्रभाव से प्रभावशील हो गया है।

जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश में उल्लेखनीय किया है कि दैनिक समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से यह संज्ञान में आया है कि कम उम्र के बच्चों एवं युवा पीढ़ी द्वारा कॉरेक्स कफ सिरप का उपयोग नशे के रूप में किया जाता है, जो कि सामान्य उपयोग की वस्तु होने से आसानी से बाजार में सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध हो जाती है। कम उम्र के बच्चों एवं युवाओं द्वारा अज्ञानतावश कॉरेक्स कप सिरप का नशे के रूप में उपयोग किया जाना, एक आम समस्या होती जा रही है, जिसके दुष्परिणाम बच्चों एवं युवाओं के शारीरिक एवं मानसिक विकास में बाधा के रुप में परिलक्षित होते हैं। नाबालिक एवं कम उम्र के बच्चों एवं युवाओं को उक्त नशे का आदी बनाया जाकर अपराध की दिशा में भी अन्य लोगों द्वारा दिग्भ्रमित किए जाने की पूर्ण संभावना रहती है। उक्त कारणों से नाबालिग बच्चों एवं युवाओं के शारीरिक एवं मानसिक दुष्प्रभाव, सड़क दुर्घटना से मृत्यु एवं जनहानि एवं अपराधिक गतिविधियों की संभावनाएँ है।कलेक्टर ने आदेश में कहा कि दैनिक समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त सूचनाओं से मुझे यह समाधान हो गया है कि नशे के रूप में नाबालिग बच्चों / कम उम्र के बच्चों एवं युवाओं द्वारा कॉरेक्स कफ सिरप जैसे उत्पाद का उपयोग नशे के लिए किया जा रहा है, जिस पर अंकुश लगाने एवं लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया जाना आवश्यक है। अतः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सम्पूर्ण मऊगंज जिले में निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। मऊगंज जिले में कोई भी दुकानदार कॉरेक्स कफ सिरप पंजीकृत चिकित्सक के नवीन प्रिस्क्रिप्शन के बिना विकय नहीं करेगा।

यह आदेश सर्व साधारण को सम्बोधित है एवं परिस्थितियों ऐसी है कि समय अभाव के कारण सर्वसाधारण को सूचना तामील नहीं की जा सकती और न ही सर्व साधारण से आपत्तियों प्राप्त की जा सकती हैं। अतः यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 (2) के अन्तर्गत एक पक्षीय पारित किया गया है। आदेश का प्रचार-प्रसार स्थानीय समाचार पत्रों/इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति / दुकानदार के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 तथा अन्य समस्त प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

जल गंगा संवर्धन अभियान से हर पंचायत में दो जल संरक्षण कार्य कराएं - कलेक्टर

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि अभियान से जुड़े विभागों द्वारा 30 मार्च से 30 जून तक की अवधि में जल संरक्षण के कार्यों की पूरी कार्य योजना बनाई गई है। कार्य योजना के अनुसार जिले भर में जल संरक्षण के कार्य कराएं। जल संरक्षण के लिए प्रत्येक नगरीय निकाय तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत में जागरूकता अभियान चलाएं। जल गंगा संवर्धन अभियान में स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों तथा आमजनों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। अभियान के दौरान प्रत्येक ग्राम पंचायत में जल संरक्षण के कम से कम दो कार्य अवश्य कराएं। पर्याप्त भूमि उपलब्ध होने तथा तकनीकी रूप से उपयुक्त स्थल होने पर अमृत सरोवरों का निर्माण कार्य कराएं। जिले के लिए निर्धारित 18 सरोवरों के निर्माण के लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तकनीकी और प्रशासकीय स्वीकृति जारी कराएं। कार्य योजना में शामिल 1219 खेत तालाबों के निर्माण के लिए हितग्राहियों का चयन करके इनकी भी प्रशासकीय और तकनीकी स्वीकृति जारी करें।

कलेक्टर ने कहा कि कार्यपालन यंत्री जल संसाधन अभियान के दौरान सभी प्रमुख नहरों की साफ-सफाई तथा सुधार के कार्य प्राथमिकता से कराएं। कार्यों की प्रगति का फोटोग्राफ सहित प्रतिवेदन हर सप्ताह प्रस्तुत

करें। पोर्टल पर भी ऑनलाइन जानकारी दर्ज कराएं। कार्यपालन यंत्री पीएचई सभी हैण्डपंपों में पानी के रिचार्ज संरचना का निर्माण कराने के लिए अभियान शुरू करें। ग्राम पंचायतों के सहयोग से सभी हैण्डपंपों में रिचार्ज संरचना का निर्माण कराएं। जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मनरेगा योजना से पूर्व से स्वीकृत जल संरक्षण के अधूरे कार्यों को पूरा कराकर उनका पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करें। जनपद में जल संरक्षण के कार्यों में अन्य विभागों से समन्वय बनाकर कार्य पूरा कराएं। आयुक्त नगर निगम तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी सभी पक्के भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से लगवाएं। इससे जल संरक्षण के साथ-साथ स्वच्छता को भी बढ़ावा मिलेगा। उप संचालक कृषि, सहायक संचालक उद्यानिकी तथा औद्योगिक विकास निगम के अधिकारी शासन के निर्देशों के अनुसार जल संरक्षण के कार्य कराएं। सभी अधिकारी साप्ताहिक टीएल बैठक में जल गंगा संवर्धन अभियान की प्रगति की जानकारी दें।

बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर ने बताया कि सभी विकासखण्डों में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जल संरक्षण के कार्य कराए जा रहे हैं। लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा कुल 18208 जल संरक्षण के कार्य कराए जा रहे हैं। इनमें 916 हैण्डपंपों में पानी के रिचार्ज की सरंचनाओं के निर्माण कार्य शामिल हैं। खेत तालाब निर्माण के लिए माडल टीएस जारी कर दिया गया है। अमृत सरोवरों के निर्माण के लिए भी प्रशासकीय और तकनीकी स्वीकृति जारी कर दी गई है। अभियान के दौरान नल जल योजनाओं की पाइपलाइन में सुधार तथा जल संसाधन विभाग द्वारा नहरों की साफ-सफाई के कार्य भी कराए जा रहे हैं। सभी शिक्षण संस्थाओं में जल संरक्षण विषय पर निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता तथा अन्य जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाएगा। बैठक में आयुक्त नगर निगम डॉ सौरभ सोनवड़े, अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी, संयुक्त कलेक्टर पीके पाण्डेय, संयुक्त कलेक्टर श्रेयस गोखले, सभी एसडीएम, जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

पोषण पखवाड़ा 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। वर्ष 2025 में सांतवें पोषण कार्यक्रम के तहत 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया जायेगा। मऊगंज कलेक्टर संजय कुमार जैन ने जिले में पोषण पखवाड़ा में निर्धारित थीम पर गतिविधियों के आयोजन के निर्देश दिये। उन्होंने जीवन के प्रथम 1000 दिवस केन्द्रित गतिविधियों, पोषण ट्रैकर में लाभार्थी माडयूल को लोकप्रिय बनाने हेतु प्रचार प्रसार किये जाने, सामुदायिक आधारित पोषण प्रबंधन माडयूल के माध्यम से कुपोषण का प्रबंधन करने सहित बच्चों में मोटापे को दूर करने के लिये स्वस्थ्य जीवन शैली अपनाने हेतु गतिविधि आयोजन के निर्देश दिये हैं।

लोकमाता देवी अहिल्या बाई की जयंती पर होंगी विभिन्न गतिविधियां

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। शासन के निर्देशानुसार लोकमाता देवी अहिल्याबाई के 300वीं जयंती वर्ष पर संपूर्ण राज्य एवं उन सभी धार्मिक नगरों जहां लोकमाता देवी अहिल्याबाई की ओर से विभिन्न कार्य कराए गए हैं, उन स्थलों पर प्रेरणा उत्सव के रूप में विविध सांस्कृतिक-अकादमिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक स्वरूप की गतिविधियां संबंधित विभागों के माध्यम से की जाएगी। मार्च माह से 31 मई तक ऐसे सभी स्थानों पर लोकमाता देवी अहिल्याबाई के जीवन/अवदान से संबंधित गतिविधियां कैलेंडर एवं कार्ययोजना अनुसार विविध गतिविधियां की जाएगी। कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए जिला स्तर पर आयोजन को पूर्ण कराने के लिए समुचित कार्यवाही के निर्देश दिये है।

4 लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रघुराजनगर (नगरीय) सतना राहुल सिलाडिया द्वारा तहसील रघुराजनगर अंतर्गत सेजहटा निवासी अमर साकेत की नहर के पानी में डूबने से हुई मृत्यु पर उसके पुत्र-पुत्रियों को समान भाग में कुल 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। इसके तहत उनके पुत्र आशिक साकेत को 1 लाख 33 हजार 334 रूपये, पुत्र अनुराग साकेत और पुत्री शीतल साकेत प्रत्येक को 1 लाख 33 हजार 333 रूपये के मान से कुल 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

महाविद्यालय के लिये भूमि आवंटित

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सतीश कुमार एस द्वारा कोठी तहसील के मौजा सगरा की आ0नं0 59/2 रकवा 7.4700, आराजी नम्बर 58/2 रकवा 4.7840 हे0 का अंश रकवा 5.000 हे0 भूमि शासकीय महाविद्यालय कोठी के नवीन भवन निर्माण हेतु उच्च शिक्षा विभाग को भूमि आवंटित की गई है। भूमि शासकीय अभिलेख में दुरस्त कराने और संबंधित विभाग को विधिवत कब्जा सौपने के निर्देश अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ग्रामीण रघुराजनगर को दिए गए हैं।

अस्पताल के लिये भूमि आवंटित

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सतीश कुमार एस द्वारा रघुराजनगर तहसील के मौजा सतना की आ0नं0 50 रकवा 5.924 हे0 का अंश रकवा 3500 वर्ग फीट भूमि शासकीय होम्योपैथी औषधालय सतना के भवन निर्माण हेतु म.प्र. शासन आयुष विभाग को भूमि आवंटित की गई है। भूमि शासकीय अभिलेख में दुरस्त कराने तथा भूमि का अधिपत्य जिला आयुष अधिकारी सतना को सौपने के निर्देश अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नगरीय रघुराजनगर को दिए गए हैं।

राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी सतना आयेंगी

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। प्रदेश की नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी 4 अप्रैल को प्रातः 6.30 बजे रेवांचल एक्सप्रेस से सतना आयेंगी।

रोगी कल्याण समिति की बैठक 8 को

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समिति जिला चिकित्सालय सतना के कार्यकारिणी समिति की बैठक 8 अप्रैल 2025 को सायं 6 बजे जिला चिकित्सालय सतना के सभाकक्ष में आयोजित की गई है। सिविल सर्जन जिला चिकित्सालय एवं सचिव रोगी कल्याण समिति डॉ. मनोज शुक्ला ने समिति के सदस्यों से बैठक में उपस्थित होने का आग्रह किया है।

उप मुख्यमंत्री देवडा आज मैहर आयेंगे

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा 4 अप्रैल को प्रातः 5.38 बजे रेवांचल एक्सप्रेस से मैहर पहुंचकर स्थानीय कार्यक्र म में शामिल होंगे। इसके बाद उप मुख्यमंत्री श्री देवडा दोपहर 12 बजे सडक मार्ग से रीवा के लिए प्रस्थान करेंगे।

न्यायालीन प्रकरणों में ई-फाइलिंग 3.0 साफ्टवेयर का उपयोग अनिवार्य

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। राज्य शासन द्वारा शासन से संबंधित समस्त न्यायालीन प्रकरणो की ई-फाइलिंग के लिए ई-फाइलिंग 3.0 साफ्टवेयर को अनिवार्य रूप से उपयोग करने के निर्देश दिये गये हैं। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ई-कोर्ट समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार शासन से संबंधित समस्त न्यायालीन प्रकरणों की ई-फाइलिंग के लिए ई-फाइलिंग 3.0 साफ्टवेयर का उपयोग किया जाना अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार न्यायालीन प्रकरणों में जबावदावा दायर करने के लिए अनिवार्य रूप से ई-फाइलिंग 3.0 साफ्टवेयर का उपयोग किया जायेगा। ई-फाइलिंग में किसी भी प्रकार की समस्या आने पर उच्च न्यायालय म.प्र. के मिस्ड काल सुविधा नम्बर 9606151400 तथा उच्च न्यायालय के हेल्पडेस्क पर ईमेल का उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ म.प्र. स्टेट इलेक्ट्रानिक डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड से भी सम्पर्क किया जा सकता है। कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने जिले के समस्त विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि शासन के निर्देशानुसार म.प्र. शासन से संबंधित समस्त न्यायालीन प्रकरणों की ई-फाइलिंग करने के लिए न्यायालय में जबावदावा दायर करने के लिए ई-फाइलिंग 3.0 साफ्टवेयर का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें।

एक लाख 25 हजार 631 किसानों से 10 लाख 25 हजार मीट्रिक टन से अधिक हुई गेहूँ खरीदी : खाद्य मंत्री श्री राजपूत

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पूरे प्रदेश में अभी तक एक लाख 25 हजार 631 किसानों से 10 लाख 25 हजार 735 मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन किया

जा चुका है। किसानों को उपार्जित गेहूँ का भुगतान भी लगातार किया जा रहा है। अभी तक 1794 करोड़ 82 लाख रूपये का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रूपये है और राज्य सरकार द्वारा 175 रूपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जा रहा है। इस तरह से गेहूँ की खरीदी 2600 रूपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है। जिला उज्जैन में एक लाख 93 हजार 362, सीहोर में एक लाख 61 हजार 737, देवास में 90 हजार 740, शाजापुर में 92 हजार 613, इंदौर में 69 हजार 558, भोपाल में 74 हजार 75, राजगढ़ में 66 हजार 47, मंदसौर 42 हजार 909, आगर मालवा में 40 हजार 550, धार में 33 हजार 249, विदिशा में 54 हजार 474, हरदा में 24 हजार 45, खण्डवा में 16 हजार 654, रतलाम में 19 हजार 743, नीमच में 6362, नर्मदापुरम में 8140, झाबुआ में 5710, रायसेन में 14183, बैतूल में 2431, दमोह में 3557, खरगौन में 565, गुना में 1057, सागर में 1053, नरसिंहपुर में 221, छिंदवाड़ा में 185, अशोकनगर में 119, सिवनी में 1313, सतना में 926, मण्डला में 90, दतिया में 43 और अलीराजपुर में 24, मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन किया जा चुका है। इस वर्ष अभी तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिये 15 लाख 9 हजार से अधिक किसानों ने पंजीयन करवाया है। किसान अब 9 अप्रैल तक पंजीयन करा सकते हैं।

विचार

वक़्फ़ संशोधन बिल 2025 लोकसभा में पारित

विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के लोकतंत्र के मंदिर रूपी संसद व उच्च सदन राज्यसभा में किसी महत्वपूर्ण विधेयक पर बहस कर उसमें संशोधन से लेकर वोटिंग तक पर पूरी प्रक्रिया को भारत सहित पूरे विश्व नें ध्यान से देखा व सुना है, जिसमें महिला आरक्षण विधेयक बिल, जीएसटी बिल, आर्टिकल 370 बिल सहित अनेकों बिलो को हमने लोकसभा के दोनों सदनों से पास होते हमने देखा है। आज यह चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज अर्ली मॉर्निंग करीब 4 बजे तक मैंनें करीब 16 घंटे लगातार वक़्फ़ (संशोधन) बिल 2025 की पूरी बहस, वोटिंग प्रक्रिया व अमेंडमेंट पर वोटिंग प्रक्रिया पर पर मैं नजर रखी। मैंने लगातार 16 घंटे संचार माध्यमों से जुड़ा रहा, क्योंकि ऐसे विषय पर लाइव देखकर रिपोर्टिंग बनाना मेरी रुचि रही है। मैंने देखा कि विपक्ष व पक्ष के सदस्यों ने ध्रुवीकरण बोलने पर विशेष ध्यान दिया विपक्ष के नेताओं ने ध्रुवीकरण पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे बहस के दौरान मैंने एक बात देखी कि एक सदस्य वाली पार्टी को भी बोलने का अधिकार दिया गया था, जिसमें चंद्रशेखर, पप्पू यादव, असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल थे। ओवैसी साहब ने बिल को फाड़ने की बात तो की,लेकिन बिल को फाड़ नहीं पाए बल्कि दो भागों को स्टेपलर की पिन खोलकर अलग किया। बहस पूरी हो जाने के बाद जेपीसी अध्यक्ष ने उसका जवाब दिया, फिर अंत में अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री ने बहस का जवाब दिया। मैंने महसूस किया कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही पूरी तैयारी के साथ बहस में शामिल होने,बहस की प्रक्रिया हो जाने के बाद माननीय सदस्यों द्वारा 100 से अधिक संशोधनों जो दर्ज कराए गए थे, उसमें तीन संशोधन की वोटिंग मशीन से वोटिंग हुई व बाकी 100 से अधिक संशोधनों को ध्वनि मत से जिसमें करीब-करीब विपक्ष के सभी संशोधन खारिज कर दिए गए। विशेष बात यह रही कि मैं पिछले 10-12 सालों में मैंने रात्रि 2-3 बजे तक संसद चलने और विधेयक पारित होने की प्रक्रिया नहीं देखी थी। वक़्फ़ (संशोधन) विधेयक, 2025 रात 1.56 बजे लोकसभा में पारित हुआ। विधेयक पर 1 घंटे 50 मिनट तक वोटिंग चली। विधेयक के समर्थन में 288 वोट पड़े, जबकि विरोध में 232 वोट पड़े। अनेक संशोधन में एक संशोधन पर इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से मतदान के बाद कुल 464 वोट दर्ज किए गए। विधेयक के पक्ष में 273 और विरोध में 191 मत पड़े। शुद्धि के बाद स्पीकर ओम बिरला आधिकारिक आंकड़ों का एलान करेंगे। लोकसभा संसद सदस्यों द्वारा दिए गए संशोधन में सबसे महत्वपूर्ण संशोधन बोर्ड में शामिल होने वाले 11 गैरमुस्लिम सदस्यों वाला संशोधन 288 के मुकाबले 231 मतों से गिर गया, यानि अब गैरमुस्लिम सदस्य बोर्ड में शामिल होंगे।वक़्फ़ (संशोधन) बिल 2025 आज ही उच्चसदन यानें राज्यसभा में पेश होगा उम्मीद है बहस के बाद इस सदन में भी वक़्त (संशोधन) बिल 2025 पारित हो जाएगा ऐसा मेरा मानना है।

मथुरा-काशी से जुड़ी नई मुहिम का आह्वान

हिंदू समूहों का दावा है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मथुरा में श्रीकृष्ण मंदिर और वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर को नष्ट करके उनके ऊपर मस्जिदें बना दीं। इसीलिये विश्व हिंदू परिषद और साधु-संतों ने 1984 में तीन मंदिरों की बात की थी, जिनमें में अयोध्या में श्रीराम मन्दिर बन चुका है। इसके बाद कई लोगों को लगने लगा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व उसके अन्य सहयोगी संगठन इससे संतुष्ट हो चुके हैं और काशी व मथुरा के विषय को जैसे उन्होंने त्याग दिया है या भूला दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, लोकसभा में वफ विधेयक के पेश किए जाने से कुछ ही घंटे पहले संघ के सरकार्यवाह एवं महामंत्री दात्रेय होसबाले ने काशी ज्ञानवापी और मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़े आंदोलनों-कार्यक्रमों में संघ के स्वयंसेवकों को न रोकने की बात कह कर एक नई मुहीम के आह्वान का अप्रत्यक्ष रूप से संकेत दे दिया है, जिसके गहरे राजनीतिक निहितार्थ हैं।

पिछले कुछ समय से इनको लेकर एक ऊहापोह की स्थिति थी, लेकिन संघ के इस मुद्दे पर छाये धुंधलको को हटाते हुए अपने नये बयान से ऊर्जा का संचार किया है। भले ही इससे राजनीति गर्माये, लेकिन हिन्दू आस्था को इससे खुशी मिली है।

संघ की कन्नड़ साप्ताहिक पत्रिका विक्रमा को दिए इंटरव्यू में होसबाले ने साफ कर दिया कि उस समय यानी 1984 में विश्व हिंदू परिषद और साधु-संतों ने तीन मंदिरों की बात की थी। इसलिए अगर संघ के स्वयंसेवक इन मंदिरों के लिए काम करना चाहते हैं, तो हम उनको रोकेंगे नहीं। साफ है, इस बयान के बाद इन मथुरा-काशी दोनों स्थलों से जुड़े विवाद और इनके आंदोलनों को एक नई ऊर्जा, इन मन्दिरों के जीर्णोद्धार, स्वतंत्र अस्तित्व हासिल करने में सफलता मिलेगी। इससे एक बार फिर भाजपा की ताकत बढ़ेगी एवं हिन्दुओं को एकजुट करने का वातावरण बनेगा। बिहार में कुछ ही माह बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और साल 2027 की शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे। बिहार एवं उत्तर प्रदेश दोनों ही प्रदेशों में जातिगत गणना और आरक्षण को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिशें हो रही हैं। इन दोनों चुनावों में काशी और मथुरा बड़ा मुद्दा बने, तो कोई आश्चर्य नहीं है। दोनों मन्दिर बिहार से सटे उत्तर प्रदेश के दो छोरों पर स्थित हिंदुओं के दो बड़े पवित्र एवं पावन धर्मस्थल हैं। मथुरा में श्रीकृष्ण मंदिर भगवान कृष्ण के जन्मस्थान के रूप में और वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के रूप में हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण आस्था-स्थल हैं, जहाँ लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए आते हैं। दोनों मंदिर हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और करोड़ो भक्तों को आकर्षित करते हैं, दोनों मंदिर भारतीय संस्कृति और इतिहास का अहम हिस्सा हैं और उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं।

काशी में विश्वनाथ और मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर का पुनरुद्धार केवल भौतिक संरचनाओं को पुनर्स्थापित करने का प्रयास नहीं है-यह भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सार को पुनर्जीवित करने एवं आहत हिन्दू आस्था पर मरहम लगाने का आह्वान है। सनातन धर्म की शाश्वत विरासत के प्रतीक ये मंदिर आक्रमणकारियों के सदियों के हमलों के बावजूद हिंदुओं की दृढ़ता और भक्ति के प्रमाण हैं। इन पवित्र स्थलों को पुन: प्राप्त करना हमारे पूर्वजों के बलिदान का सम्मान करने, हमारी विरासत को संरक्षित करने और हमारी समृद्ध परंपराओं को आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाने का कार्य है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंदू मंदिरों के बारे में सच्चाई सबके सामने है, लेकिन ये मामले अनसुलझे हैं। ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के ये स्थल लंबी अदालती लड़ाई के बावजूद अभी भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं।

दत्तात्रेय होसबले का यह साक्षात्कार महत्वपूर्ण होने के साथ दूरगामी सोच से जुड़ा है। हालांकि, होसबले ने अपने इसी इंटरव्यू में देश की सभी मस्जिदों को मुद्दा बनाने की प्रवृत्ति को सामाजिक ताने-बाने के लिए नुकसानदेह बताकर संतुलन साधने की कोशिश की है। इससे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग तलाशना सही नहीं है। भले ही पिछले साल दिसंबर में मस्जिदों को लेकर उठ रहे विवाद को शांत करने का उन्होंने यह प्रयास किया था। लेकिन काशी और मथुरा भी उसमें शामिल रहे हो, ऐसा कैसे सोचा जा सकता है? होसबले ने इस साक्षात्कार में गौ हत्या, लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी चिंताओं को स्वीकार किया। उन्होंने अस्पृश्यता यानी छुआछूत को खत्म करने, युवाओं में संस्कृति के संरक्षण और देशी भाषाओं की सुरक्षा जैसे समकालीन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। भाषा नीति पर होसबाले ने त्रिभाषी दृष्टिकोण का समर्थन किया और इसे 95 प्रतिशत भाषाई विवादों का समाधान बताया। उन्होंने भारतीय भाषाओं के संरक्षण और उनमें शिक्षित लोगों के लिए आर्थिक अवसर सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया।

होसबोले ने कहा कि लोगों को यह समझना चाहिए कि वैश्विक भूराजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। यदि भारत में हिंदू समाज मजबूत और संगठित नहीं है, तो केवल 'अखंड भारत' के बारे में बोलने से परिणाम नहीं मिलेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अतीत की खोज में लगे रहने से समाज अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तनों पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा, जैसे अस्पृश्यता को समाप्त करना, युवाओं में मूल्यों का संचार करना तथा संस्कृति और भाषाओं को संरक्षित करना। निश्चित ही होसबले के बोल से जहां हिन्दू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा को बल मिला है, वहीं राष्ट्रीयता भी मजबूत होती हुई दिख रही है। संघ की स्थापना भी इसी उद्देश्य एवं राष्ट्रवादी आंदोलन को एक मजबूत सांस्कृतिक आधार देने के लिए की गई थी। हमारी सदियों पुरानी प्राचीन सभ्यताएं जो धर्म, अहिंसा और भक्ति के सिद्धांतों पर आधारित थी उपनिवेशवाद के शोर में अपनी आवाज खो न जाये, हिन्दू समाज पर रह-रह हो रहे हमले रूके, हिन्दू एवं सनातन संस्कृति को सलक्ष्य कुचलने के प्रयास विराम पाये-इन जटिल स्थितियों में भारत के लोगों को एक सांस्कृतिक छत्र के नीचे एकजुट करने की दृष्टि से होसबले ने जगाया है, चेताया है, संगठित होने का आह्वान किया है। निश्चित तौर पर इन दोनों मन्दिर मुद्दों को नए सिरे से हवा देने की इस कवायद ने संघ विरोधियों एवं मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने वालों के सामने एक नई गंभीर चुनौती पेश की है। खासकर यह देखते हुए कि अयोध्या की रणनीतिक सफलता ने हिंदुत्व की राजनीति का आधार मजबूत किया है, हिन्दुओं को संगठित किया है।

मंदिर-मस्जिद विवाद के बीच संघ की तरफ से पहले भी कई बयान आते रहे हैं। ये बयान दर्शाते हैं कि संघ भले ही सीधे-सीधे विवाद से खुद को भले ही अलग रखता हो, वैचारिक रूप से वह इनको पूरा समर्थन देता है। संघ का समर्थन देश को अराजक बनाने का कभी नहीं रहा, उसके सामने बड़ा लक्ष्य देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का भी है। बांग्लादेश समेत कई पड़ोसी देशों में भारत-विरोधी शक्तियां नए सिरे से सक्रिय होने लगी हैं, उनसे लड़ने की ताकत एवं रणनीति भी संघ चाहता है। संघ सामंजस्यपूर्ण और संगठित भारत के आदर्श को आकार देने के लिये प्रतिबद्ध है। श्रीराम जन्मभूमि मुक्ति जैसे आंदोलनों ने भारत के सभी वर्गों और क्षेत्रों को सांस्कृतिक रूप से संगठित किया। राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर सीमा सुरक्षा, शासन में सहभागिता से लेकर ग्रामीण विकास तक, राष्ट्रीय जीवन का कोई भी पहलू संघ के स्वयंसेवकों से अछूता नहीं है। सौ वर्षों की संघ यात्रा हिन्दू एकता, विश्व शांति व समृद्धि के साथ सामंजस्यपूर्ण और एकजुट भारत के भविष्य के संकल्प के साथ-साथ काशी-मथुरा के मुद्दे से भी जुड़ी है। हिंदुओं को बचाने और उन्हें सम्मान और गरिमा के साथ देश सेवा में तत्पर करने के लिये उनकी आस्था एवं अस्तित्व पर लगे घावों को तो भरना ही होगा।

कृषि क्षेत्र में करवट बदलता भारत

भारत में लगभग 60 प्रतिशत आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और अपनी आजीविका के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। जबकि, कृषि क्षेत्र का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान केवल 18 प्रतिशत के आस पास बना हुआ है। इस प्रकार, भारत में यदि गरीबी को जड़ मूल से नष्ट करना है तो कृषि के क्षेत्र में आर्थिक सुधार कार्यक्रमों को लागू करना ही होगा। भारत ने हालांकि आर्थिक क्षेत्र में पर्याप्त सफलताएं अर्जित की हैं और भारत आज विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है तथा शीघ्र ही अमेरिका एवं चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। साथ ही, भारत आज विश्व में सबसे अधिक तेज गति से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था भी बन गया है। परंतु, इसके आगे की राह अब कठिन है, क्योंकि केवल सेवा क्षेत्र एवं उद्योग क्षेत्र के बल पर और अधिक तेज गति से आगे नहीं बढ़ा जा सकता है और कृषि क्षेत्र में आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना होगा।

भारत में हालांकि कृषि क्षेत्र में कई सुधार कार्यक्रम लागू किए गए हैं और भारत आज कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया है। परंतु, अभी भी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। किसानों के पास पूंजी का अभाव रहता था और वे बहुत ऊंची ब्याज दरों पर महाजनों से ऋण लेते थे और उनके जाल में जीवन भर के लिए फंस जाते थे, परंतु, आज इस समस्या को बहुत बड़ी हद तक हल किया जा सका है और किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसान को आसान नियमों के अंतर्गत बैंकों से पर्याप्त ऋण की सुविधा उपलब्ध है और इस सुविधा का लाभ आज देश के करोड़ों किसान उठा रहे हैं। दूसरे, इसी संदर्भ में किसान सम्मान निधि योजना भी किसानों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो रही है और इस योजना का लाभ भी करोड़ों किसानों को मिल रहा है। इससे किसानों की कृषि सम्बंधी बुनियादी समस्याओं को दूर करने के सफलता मिली है।

भारतीय कृषि आज भी मानसून पर निर्भर है। देश के ग्रामीण इलाकों में सिंचाई सुविधाओं का अभाव है। इस समस्या को हल करने के उद्देश्य से भारत सरकार प्रति बूंद अधिक फसल की रणनीति पर काम कर रही है एवं सूक्ष्म सिंचाई पर बल दिया जा रहा है ताकि कृषि के क्षेत्र में पानी के उपयोग को कम किया जा सके तथा जल संरक्षण के साथ सिंचाई की लागत भी कम हो सके।

देश में कृषि जोत हेतु पर्याप्त भूमि का अभाव है और देश में सीमांत एवं छोटे किसानों की संख्या करोड़ों की संख्या में हो गई है। जिससे यह किसान किसी तरह अपना और परिवार का भरण पोषण कर पा रहे हैं इनके लिए कृषि लाभ का माध्यम नहीं रह गया है। इन तरह की समस्याओं के हल हेतु अब केंद्र सरकार विभिन्न उत्पादों के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य में, मुद्रा स्फीति को ध्यान में रखकर, वृद्धि करती रहती है, इससे किसानों को

अत्यधिक लाभ हो रहा है। भंडारण सुविधाओं (गोदामों एवं कोल्ड स्टोरेज का निर्माण) में पर्याप्त वृद्धि दर्ज हुई है एवं साथ ही परिवहन सुविधाओं में सुधार के चलते किसान कृषि उत्पादों को लाभ की दर पर बेचने में सफल हो रहे है अन्यथा इन सुविधाओं में कमी के चलते किसान अपने कृषि उत्पादों को बाजार में बहुत सस्ते दामों पर बेचने पर मजबूर हुआ करता था। खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना भारी मात्रा में की जा रही है इससे कृषि क्षेत्र में मूल्य संवर्धन को बढ़ावा मिल रहा है एवं कृषि उत्पादों की बर्बादी को रोकने में सफलता मिल रही है। आज भारत में उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के उपयोग पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि उर्वरकों के उपयोग की आवश्यकता कम हो एवं कृषि उत्पादकता बढ़े। इस संदर्भ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भी किसानों की मदद कर रही है इससे किसान कृषि भूमि पर मिट्टी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर कृषि उत्पाद कर रहे हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार को स्थापित किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि किसान सीधे ही उपभोक्ता को उचित दामों पर अपनी फसल को बेच सके। साथ ही, कृषि फसल बीमा के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि देश में सूखे, अधिक वर्षा, चक्रवात, अतिवृष्टि, अग्नि आदि जैसी प्रकृतिक आपदाओं के चलते प्रभावित हुई फसल के नुक्सान से किसानों को बचाया जा सके। आज करोड़ों की संख्या में किसान फसल बीमा योजना का लाभ उठा रहे हैं। देश में खेती किसानी का काम पूरे वर्ष भर तो रहता नहीं है अत: किसानों के लिए अतिरिक्त आय के साधन निर्मित करने के उद्देश्य से डेयरी, पशुपालन, मधु मक्खी पालन, पोल्ट्री, मत्स्य पालन आदि कृषि सहायक क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जा रहा है, ताकि किसानों को अतिरिक्त आय की सुविधा मिल सके। विश्व के विभिन्न देशों ने अपनी आर्थिक प्रगति के प्रारम्भिक चरण में कृषि क्षेत्र का ही सहारा लिया है। औद्योगिक क्रांति तो बहुत बाद में आती है इसके पूर्व कृषि क्षेत्र को विकसित अवस्था में पहुंचाना होता है। भारत में भी आज कृषि क्षेत्र, देश की अर्थव्यवस्था का आधार है, जो न केवल खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि करोड़ों नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर भी निर्मित करता है। साथ ही, औद्योगिक इकाईयों के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध कराता है। वैश्विक स्तर पर कृषि क्षेत्र की महत्ता आगे आने वाले समय में भी इसी प्रकार बनी रहेगी क्योंकि इस क्षेत्र से पूरी दुनिया के नागरिकों के लिए भोजन, उद्योग के लिए कच्चा माल एवं रोजगार के अवसर कृषि क्षेत्र से ही निकलते रहेंगे। हां, कृषि क्षेत्र में आज हो रही प्रौद्योगिकी में प्रगति के चलते किसानों को कम भूमि पर, मशीनों का उपयोग करते हुए, कम पानी की आवश्यकता के साथ भी अधिक उत्पादन करना सम्भव हो रहा है। इससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ कृषि उत्पाद की लागत कम हो रही है और किसानों के लिए खेती एक उद्योग के रूप में पनपता हुआ दिखाई दे रहा है और अब यह लाभ का व्यवसाय बनता हुआ दिखाई देने लगा है। केला, आम, अमरूद, पपीता, नींबू जैसे कई ताजे फलों एवं चना, भिंडी जैसी सब्जियों, मिर्च, अदरक जैसे प्रमुख मसालों, जूट जैसी रेशेदार फसलों, बाजरा एवं अरंडी के बीज जैसे प्रमुख खाद्य पदार्थों एवं दूध के उत्पादन में भारत पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर आ गया है। दुनिया के प्रमुख खाद्य पदार्थों यथा गेहूं एवं चावल का भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है।

भारत वर्तमान में कई सूखे मेवे, कृषि आधारित कपड़े, कच्चे माल, जड़ और कांड फसलों, दालों, मछली पालन, अंडे, नारियल, गन्ना एवं कई सब्जियों का पूरे विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत 80 प्रतिशत से अधिक कृषि उपज फसलों (काफी एवं कपास जैसी नकदी फसलों सहित) के साथ दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया था।

निगम मंडल, बोर्ड और आयोग में अध्यक्ष पदों की सूची जारी

मीडिया ऑडीटर, रायपुर ((**निप्र**))। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने बुधवार को निगम मंडल, बोर्ड और आयोग में अध्यक्ष पदों की सूची जारी कर दी है। प्रदेश भाजपा के 36 नेताओं को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जैसे पद दिए गए हैं। इनमें से 15 ओबीसी वर्ग के नेता हैं। सतनामी समुदाय से किसी नेता को जगह नहीं मिली है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर कार्यकर्ताओं ने नाराजगी भी जताई है। लिस्ट में 3 अल्पसंख्यक और 4 आदिवासी नेता भी शामिल हैं। खास बात यह है की सूची में शामिल बड़े निगम मंडल उन नेताओं को दिए गए हैं, जिन्हें पिछले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। सूची सामने आने के बाद बहुत से नेता और कार्यकर्ता खुले तौर पर तो कुछ दबी जुबान में अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। नियुक्तियों की बात करें तो भूपेंद्र सवन्नी को क्रेडा, संजय श्रीवास्तव को नान, सौरभ सिंह को खनिज विकास निगम और दीपक म्हस्के को ष्टत्रस्ष्ट की जिम्मेदारी दी गई है। जबकि केदार गुप्ता को दुग्ध महासंघ की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इसके अलावा राजीव अग्रवाल को छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलॅपमेंट कार्पोरेशन का चेयरमेन बनाया गया है। ब्रेवरेज कॉरपोरेशन और फिल्म विकास निगम का फैसला नहीं लिया जा सका है। अब-जब निगम मंडल की सूची आ चुकी है तो दूसरी सबसे बड़ी चर्चा मंत्रिमंडल में बदलाव की है। खबर है कि प्रदेश में अमित शाह के दौरे के बाद मंत्रिमंडल में 2 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। सूची को लेकर भारतीय जनता पार्टी सूत्रों का कहना है कि सक्रिय तौर पर संगठन के कामों में शामिल रहे नेताओं को निगम मंडल में तवज्जो दी गई है। संगठन का सदस्यता अभियान, पिछली कांग्रेस सरकार के समय के किए गए आंदोलन में भूमिका, निकाय चुनाव में अलग-अलग जीत दिलाने वालों को पद दिए गए हैं। संजय श्रीवास्तव, श्रीनिवास राव मद्दी, अमरजीत सिंह छाबड़ा जैसे नेताओं को पार्टी में अलग-अलग कार्यक्रमों में बेहतर प्रदर्शन की वजह से निगम मंडल में जगह मिली है। निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज रहे कुछ नेताओं को भी एडजस्ट किया गया है। रायपुर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नंदकुमार साहू को बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के रायपुर ग्रामीण विधानसभा सीट से चुनाव हार चुके साहू को यह पद दिया गया है। राजीव अग्रवाल पार्षद चुनाव नहीं जीत पाए थे।नंदे साहू, सौरभ सिंह, अनुराग सिंहदेव विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, राजीव अग्रवाल पार्षद चुनाव नहीं जीत पाए थे। रायपुर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नंदकुमार साहू को बनाया गया है। गौरी शंकर श्रीवास ने खुले तौर पर निगम मंडल में दिए गए पद को ठुकरा दिया है। गौरी शंकर श्रीवास को छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने इसे लेकर सोशल मीडिया पर लिखा कि पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है कि जिसे उठाने में मेरे कंधे असमर्थ हैं। इसलिए पद स्वीकार नहीं संगठन के कार्यकर्ता के रूप में ठीक हूं धन्यवाद।

इस सोशल मीडिया पोस्ट ने नई बहस को जन्म दे दिया है, भाजपा के कई नाराज कार्यकर्ता और नेता श्रीवास के समर्थन में आ गए हैं। निगम मंडल की सूची में एक नाम चौंकाने वाला था और वह था प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री राम सेवक पैंकरा का। लंबे वक्त से सक्रिय राजनीति से करीब करीब गायब रहे, अचानक निगम मंडल की सूची में उनका नाम हैरान कर गया। रामसेवक पैंकरा को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया है इनके अलावा सूची में विकास मरकाम, रामप्रताप सिंह, सुरेंद्र कुमार बेसरा भी वो आदिवासी नेता हैं, जिन्हें निगम-मंडल में पद मिले हैं। पैंकरा और रामप्रताप सिंह को वापस सक्रिय करने के पीछे चर्चा यह है कि सरगुजा में शक्ति का संतुलन बनाए रखा जा सके।

बॉयफ्रेंड ने चाचा के साथ मिलकर किया गैंगरेप

मीडिया ऑडीटर, बिलासपुर (निप्र)। बिलासपुर में युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए बुलाया। उसके भरोसे में आकर युवती उसके घर पहुंची, तब युवक ने अपने चाचा के साथ मिलकर उससे गैंगरेप किया। उनके चंगुल से छूटकर युवती ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला तोरवा थाना क्षेत्र का है। दरअसल, तोरवा क्षेत्र में रहने वाली 23 वर्षीय युवती और देवरीखुर्द के सतबहनिया मंदिर के पास रहने वाले राजऋषि सिंह (32) के बीच दोस्ती थी। दोनों आपस में बातचीत करते थे। फिर युवक ने उससे प्यार का इजहार किया। युवती भी उसकी बातों में आ गई। युवक ने उसके साथ शादी करने का वादा किया था। युवती अपने प्रेमी राजऋषि के भरोसे में आ गई। युवक ने उससे मिलने बुलाया और शादी करने का झांसा दिया। युवक की बातों में आकर युवती उसके साथ चली गई। 1 अप्रैल को युवक उसे लेकर अपने चाचा सुरेंद्र कुमार सिंह (56) के घर नहरपारा सफेद खदान गया। जहां पहले युवक ने शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान उसका चाचा भी वहां मौजूद था। उसकी नीयत खराब हो गई। दोनों ने युवती बंधक बना लिया। डराया-धमकाया और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद चाचा-भतीजे ने युवती से गैंगरेप किया। डरी सहमी युवती किसी तरह आरोपियों के चंगुल से छूटकर भागी। युवती ने 2 अप्रैल बुधवार को पूरे मामले की शिकायत तोरवा थाने में की। गैंगरेप का मामला सामने आने पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी।तोरवा थाना प्रभारी अभय बैस ने बताया कि आरोपी राजऋषि और उसके चाचा सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा

ग्रामीणों का मुफ्त इलाज, मोबाइल मेडिकल यूनिट में 42 तरह की जांच

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी ((**निप्र**))। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र में दो मोबाइल मेडिकल यूनिट की सेवाएं दी जा रही हैं। मोबाइल यूनिट रोजाना सुबह 8 बजे से शाम 3 बजे तक विभिन्न वार्डों में कैंप लगाती है। यहां मरीजों की 42 प्रकार की जांच की जाती है। साथ ही मुफ्त दवाएं भी दी जाती हैं। हाल ही में वार्ड क्रमांक 5, आर्टिशियन ब्लॉक वेस्ट चिरमिरी में लगे कैंप में 63 मरीजों की जांच की गई। इनमें 25 महिलाएं और 18 पुरुष शामिल थे। 16 मरीजों के लैब टेस्ट किए गए और 62 मरीजों को दवाएं वितरित की गईं। नगर निगम चिरमिरी के आयुक्त रामप्रसाद आचला ने बताया कि इस योजना से लोगों को घर के पास ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। वे नियमित रूप से इस सेवा की मॉनिटरिंग करते हैं। कैंप में डॉ. किरण किशोर, डॉ. सुमन पांडेय, एएनएम सुनिता कारफारमा, लैब टेक्नीशियन सुशील यादव, फार्मासिस्ट नैन्सी, सुभाष, रोशन सिंह और लैब टेक्नीशियन अलमा एक्का सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा।

सतनामी समुदाय से किसी नेता को जगह नहीं

मीडिया ऑडीटर, रायपुर ((**निप्र**))। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने बुधवार को निगम मंडल, बोर्ड और आयोग में अध्यक्ष पदों की सूची जारी कर दी है। प्रदेश भाजपा के 36 नेताओं को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जैसे पद दिए गए हैं। इनमें से 15 ओबीसी वर्ग के नेता हैं। सतनामी समुदाय से किसी नेता को जगह नहीं मिली है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर कार्यकर्ताओं ने नाराजगी भी जताई है। लिस्ट में 3 अल्पसंख्यक और 4 आदिवासी नेता भी शामिल हैं। खास बात यह है की सूची में शामिल बड़े निगनियुक्तियों की बात करें तो भूपेंद्र सवन्नी को क्रेडा, संजय श्रीवास्तव को नान, सौरभ सिंह को खनिज विकास निगम और दीपक म्हस्के को ष्टत्रस्ष्ट की जिम्मेदारी दी गई है। जबकि केदार गुप्ता को दुग्ध महासंघ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा राजीव अग्रवाल को छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलॅपमेंट कार्पोरेशन का चेयरमेन बनाया गया है। ब्रेवरेज कॉरपोरेशन और फिल्म विकास निगम का फैसला नहीं लिया जा सका है। अब-जब निगम मंडल की सूची आ चुकी है तो दूसरी सबसे बड़ी चर्चा मंत्रिमंडल में बदलाव की है। खबर है कि प्रदेश में अमित शाह के दौरे के बाद मंत्रिमंडल में 2 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। सूची को लेकर भारतीय जनता पार्टी सूत्रों का कहना है कि सक्रिय तौर पर संगठन के कामों में शामिल रहे नेताओं को निगम मंडल में तवज्जो दी गई है। संगठन का सदस्यता अभियान, पिछली कांग्रेस सरकार के समय के किए गए आंदोलन में भूमिका, निकाय चुनाव में अलग-अलग जीत दिलाने वालों को पद दिए गए हैं। संजय श्रीवास्तव, श्रीनिवास राव मद्दी, अमरजीत सिंह छाबड़ा जैसे नेताओं को पार्टी में अलग-अलग कार्यक्रमों में बेहतर प्रदर्शन की वजह से निगम मंडल में जगह मिली है। निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज रहे कुछ नेताओं को भी एडजस्ट किया गया है। नंदे साहू, सौरभ सिंह, अनुराग सिंहदेव विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, राजीव अग्रवाल पार्षद चुनाव नहीं जीत पाए थे। रायपुर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नंदकुमार साहू को बनाया गया है।

इनोवा कार से 38 किलो गांजा जब्त, दो गिरफ्तार

मीडिया ऑडीटर, सरगुजा (निप्र)। सरगुजा पुलिस ने इनोवा कार से 38 किलो गांजा के साथ दो युवकों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने गांजे की कीमत 9.50 लाख रुपए बताई है। ओडिशा से गांजा लाया गया था। एसपी ने बताया कि आरोपी गांजा की तस्करी करते हुए बाहर ले जाने की फिराक में थे, जिन्हें पकड़ लिया गया है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, बुधवार रात कोतवाली पुलिस ने अंबिकापुर-रायगढ़ मार्ग पर जांच के दौरान एक इनोवा कार को रोका। पुलिस ने इनोवा कार की जांच की तो कार में बोरों में भरे हुए गांजे के पैकेट मिले। पुलिस ने कार सवार दो युवकों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने इनोवा कार को भी जब्त किया है। एसपी योगेश पटेल ने बताया कि, पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इनोवा कार कार क्रमांक सीजी 16 सीएल 1858 की जांच की, जिस दौरान यह गांजा जब्त किया गया। आरोपियों ने गांजा ओडिशा से लाना बताया है। वे तस्करी के लिए इस मार्ग का उपयोग कर रहे थे। गांजा बाहर खपाया जाना था। एसपी ने बताया कि मामले में अन्य आरोपियों की पतासाजी कर रही है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। सरगुजा गांजे की तस्करी के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख मार्गों में से एक है। ओडिशा से रायगढ़ और जशपुर के रास्ते गांजा तस्कर गांजा लेकर सरगुजा आते हैं। यहां से गांजा यूपी और मध्यप्रदेश के लिए भेजा जाता है। सरगुजा और बलरामपुर में इसके पहले भी गांजे की बड़ी खेप पकड़ी गई है।

कांग्रेस की सरकार बनी तो केस खत्म करेंगे

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में 10 जून 2024 को हुई आगजनी और हिंसा मामले की बुधवार को जिला न्यायालय में सुनवाई हुई। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव समेत 7 लोगों पर आरोप तय किए गए हैं। जिला कोर्ट में आरोप तय किए जाने के बाद इन पर बलौदाबाजार आगजनी कांड के आरोपी के रूप में मुकदमा चलेगा। इधर, कोर्ट में पेश होने के बाद विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। सरकार ने निर्दोष लोगों को फंसाया है, लेकिन ट्रायल शुरू होने के बाद सभी निर्दोष साबित होंगे। अगर कांग्रेस की सरकार बनी, तो इस केस को पूरी तरह खत्म किया जाएगा। इस मामले में विधायक देवेंद्र यादव के अलावा दिनेश कुमार चतुर्वेदी, मोहन बंजारे, किशोर नौरंगे, राजकुमार सतनामी, ओमप्रकाश बंजारे और नितेश उर्फ निक्कू टंडन को आरोपी बनाया गया है। इधर, कोर्ट में पेश होने के बाद विधायक देवेंद्र यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा, बलौदाबाजार कांड में जिस तरह से प्रशासन ने निर्दोष लोगों को जेल में डाला। 8-9 माह प्रताड़ित किया। परिवार के लोगों को परेशान किया। कोर्ट ने हमें जमानत दी, और सुप्रीम कोर्ट पर हमें पूरा भरोसा है। इस मामले में अब ट्रायल शुरू होने वाला है। हमें पूरा भरोसा है सभी बाइज्जत बरी होंगे।

साथ ही साथ हम लोग कांग्रेस पार्टी में भी यह बात रखी है। कांग्रेस की सरकार आने वाले समय में बनेगी, तब इस मामले को शून्य किया जाएगा और इस मामले को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले की जो सही जांच होनी चाहिए थी वह जांच कभी हुई नहीं, इस मामले में केवल राजनीति हुई और चिह्नित कर लोगों को जेल में डाला गया और निर्दोष लोगों को प्रताड़ित किया गया। सरकार की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक मुकुंद देशपांडे ने बताया कि दशहरा मैदान में जो आमसभा हुई थी, उसे समाज ने आंदोलन सभा का नाम दिया था। उसमें दिए गए भाषण, उकसाने और षड्यंत्र करने के कारण अपराध हुए। मामले में अभियोग पत्र पेश होने के बाद आरोपियों के खिलाफ अभियोग लगाया गया है। देवेंद्र यादव, किशोर नौरंगे, मोहन बंजारे, दिनेश कुमार चतुर्वेदी, ओमप्रकाश बंजारे, नितेश उर्फ निक्कू टंडन के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। अब गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। यह भी बताया कि मामले में सभी आरोपियों की मौजूदगी रही। सभी ने आरोपों से इनकार किया है। इसके लिए अभियोजन के तरफ से अब गवाह पेश किए जाएंगे। आरोपियों के वकील अनादि शंकर मिश्रा ने बताया कि 10 जून 2024 को बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट कार्यालय में आगजनी की घटना हुई थी, जिसमें भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव को आरोपी बनाया गया है। इस मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। सुनवाई के बाद कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 153, 505(1), 505(1) 505(1)(ष्ट), 109, 120, 147, 148, 149, 186, 353, 332, 333, 307, 435, 436, 441, 427, 201, 153 और लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 और 4 के तहत आरोप तय किया है। अब ट्रायल प्रक्रिया में अभियोजन पक्ष अपना पक्ष रखेगा, और अगली सुनवाई में अभियोजन साक्ष्य पेश किए जाएंगे।

3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई, अवैध खनन तुरंत रुकवाया

मीडिया ऑडीटर,कोरिया(एजेंसी)। कोरिया जिले के पोडी बचरा क्षेत्र में अवैध खनिज उत्खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर चंदन त्रिपाठी के निर्देश पर खनिज अधिकारी भूषण कुमार पटेल और उनकी टीम ने ग्राम बवरा का निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया गया कि तीन लोगों ने अपनी जमीन पर अवैध रूप से मिट्टी का खनन कर ईंट निर्माण किया था। इनमें सतीश जायसवाल, नरेश जायसवाल और राजेश जायसवाल शामिल हैं। खनन अमला ने मौके पर पहुंचकर तीनों को नोटिस जारी किया और अवैध खनन तुरंत बंद करवाया। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 और खान एवं खनिज अधिनियम 1957 के तहत की गई है। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान है। जिला खनिज अधिकारी ने स्पष्ट किया कि अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा। इससे जिले में खनिज संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सकेगा।

हाथी ने 4 दिन में 4 लोगों को मार डाला बलरामपुर में खेत में पानी देने गए युवक को कुचला, 2 ने भागकर बचाई जान

मीडिया ऑडीटर, बलरामपुर((**निप्र**))। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में गुरुवार की सुबह हाथी ने एक युवक को कुचलकर मार डाला। जबकि दो युवकों ने भागकर अपनी बचाई। हालांकि वो गिरकर घायल हो गए हैं। घटना सेमरसोत अभ्यारण के ग्राम पंचायत घाघरा की है। जिले में चार दिन में 4 लोगों को हाथी ने मौत के घाट उतार दिया है। जानकारी के मुताबिक, कोदौरा रेंज के घाघरा गांव के रहने वाले दिनेश पोया (35 साल) दो साथियों के साथ खेत पहुंचे थे। वे रामकरण गोंड़ (40 साल) और रोहित नागवंशी (24 साल) के साथ मक्के की फसल में पानी देने गए थे। खेत में तड़के 3 बजे से एक हाथी घुसा हुआ था। सुबह 5 बजे जब दिनेश पोया खेत पहुंचे तो खेत में उन्हें हलचल का एहसास हुआ।

जब वे आगे गए तो हाथी ने पटक-पटककर मार डाला। शोर सुनकर उसके साथी रामकरण और रोहित ने किसी तरह अपनी जान बचाई। उन्होंने गांव में ग्रामीणों को इसकी सूचना दी। जिसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तब तक दिनेश पोया की मौत हो गई थी। घटना की सूचना मिलने पर कोदौरा रेंजर, वनकर्मी और कोदौरा पुलिस मौके पर पहुंची। दिनेश पोया के शव को पंचनामा के बाद पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। दिनेश पोया शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे भी हैं। वह परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। वन विभाग ने परिजनों को तत्कालीन सहायता राशि 25 हजार दी है। वहीं लोगों को जंगल की ओर न जाने की सलाह भी दी है। हाथी पास के जंगल में मौजूद है, जिससे लोग दहशत में हैं।

बिना पूछताछ किए मकान का फोटो खींचकर वापस लौटी सीबीआई

मीडिया ऑडीटर, भिलाई ((**निप्र**))। सीबीआई की टीम गुरुवार को फिर से भिलाई पहुंची। वो भिलाई के खुर्सीपार क्षेत्र में रहने वाले भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के प्रतिनिध भोलू श्रीवास्तव के घर पहुंची। सीबीआई के अधिकारी गाड़ी से उतरे उन्होंने देखा की घर में ताला लगा है तो घर का फोटो खींचा और फिर फिर वापस लौट गई।

आपको बता दें कि महादेव ऑनलाइन सट्टा के मामले में सीबीआई की टीम लगातार दुर्ग और रायपुर के अलग-अलग ठिकानों में छापेमारी कर रही है। 3 अप्रैल की सुबह सीबीआई की टीम भिलाई नगर विधायक के प्रतिनिधि राकेश उर्फ भोलू श्रीवास्तव के घर पहुंची। टीम में सुरक्षा कर्मी और कई अधिकारी थे। टीम के अधिकारी गाड़ी से उतरे उन्होनें भोलू श्रीवास्तव के घर के बाहर खड़ी गाड़ियों और घर की फोटो वीडियोग्राफी की। उस समय घर में ताला लगा हुआ था।

टीम ने ना तो पड़ोसियों से कुछ पूछा और ना घर में कोई नोटिस चस्पा किया। फोटो वीडियोग्राफी करने के बाद पूरी टीम वापस लौट गई। भोलू श्रीवास्तव विदायक देवेंद्र यादव के काफी करीबी हैं। वो भिलाई नगर निगम की सामान्य सभा और बजट बैठक में विधायक प्रतिनिधि के रूप में शामिल होते रहे हैं। जिस समय सीबीआई की टीम वहां पहुंची उनके साथ लोकल पुलिस भी मौजूद रही।छावनी सीएसपी हरीश पाटिल ने बताया कि सीबीआई की टीम भोलू श्रीवास्तव के घर सुबह आई थी। वो भी वहां पहुंचे थे। टीम ने भोलू के घर का फोटो वीडियो खींचा और फिर वापस लौट गई। सीबीआई की टीम कुछ दिन पहले भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के घर पहुंची थी। उस दौरान विधायक के बाहर होने के चलते टीम ने उनके घर की तलाशी ली और घर वालों से पूछताछ करके लौट गई। इसके बाद अब टीम उनके विधायक प्रतिनिधि के घर पहुंची थी।

युवक बोला-उप सभापति चला रहे महादेव सट्टा निगम कांग्रेस पार्षद और उप-सभापति मन्नान गफ्फार खान पर महादेव सट्टा पैनल चलाने का आरोप लगा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधायक देवेंद्र यादव के घर महादेव सट्टा मामले में छापा मारा था। अब भिलाई नगर निगम कांग्रेस पार्षद और उप-सभापति मन्नान गफ्फार खान पर महादेव सट्टा पैनल चलाने का आरोप लगा है। युवक ने बताया कि मन्नान और उसके भाईयों ने उससे अकाउंट लिया था। बाद में बैंक से फोन आया कि लाखों के ट्रांजेक्शन हुए हैं। उसने मन्नान से अपना अकाउंट वापस करने कहा। इसके बाद युवक ने अपने अकाउंट से 10 हजार रुपए निकाले।

इससे नाराज होकर मन्नान और उसके भाइयों ने युवक को कमरे में बंद करके पीटा।

ज्यादा मजदूरी के लिए गुजरात गए, 20 मजदूरों की मौत

हरदा/देवास (एजेंसी)। दो साल पहले मेरे चाचा ससुर की मौत हो गई थी। पीछे 6 लोगों का परिवार छोड़ गए थे। चाची ने बेटे की शादी की, जिसके बाद परिवार पर 40 हजार रुपए का कर्ज हो गया था। मजदूरी करके उसी को चुकाने गुजरात गए थे। सभी 6 लोगों की मौत हो गई है। ये कहना है कृष्णा बाई का। कृष्णा बाई, केसर बाई के भतीजे की पत्नी हैं। गुजरात के बनासकांठा में मंगलवार को हुए पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में एमपी के जिन 20 मजदूरों की मौत हुई है, उनमें देवास जिले के संदलपुर गांव की केसर बाई का पूरा परिवार भी था। गांव के लोगों का कहना है कि सरकार अब मुआवजा देने की बात कर रही है लेकिन परिवार में कोई मुआवजा लेने वाला भी नहीं बचा। गुजरात की पटाखा फैक्ट्री में जिन 20 मजदूरों की मौत हुई है, वो एमपी के देवास जिले और हरदा जिले के हैं। टीम दोनों जिलों में उनके गांव पहुंची। लोगों और परिजन से जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी, जिसने इन परिवारों को न सिर्फ गुजरात पलायन के लिए मजबूर किया बल्कि इतने खतरनाक काम में भी धकेल दिया। भोपाल से करीब 135 किमी दूर देवास जिले का संदलपुर गांव है। गांव के मुख्य मार्ग पर कुछ ही दुकानें खुली नजर आईं। जिससे भी पूछा कि गुजरात में जिन मजदूरों की मौत हुई है, उनके घर कहां हैं? गांव के अंदर बसी एक गरीब बस्ती की तरफ इशारा करते हुए बता दिया। एक घर से महिलाओं के रोने की आवाज आ रही थी। सामने कुछ लोग गली में बैठे नजर आए। हम उनके पास पहुंचे और बात की।

कुशल वित्तीय प्रबंधन से संभव हो रहा है, विकास के साथ औद्योगिक गतिविधियों और जन हितैषी कार्यों का विस्तार-मुख्यमंत्री

भोपाल (एजेंसी)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश में डबल इंजन की सरकार जनहितैषी संकल्पों के साथ अग्रसर है। उद्योग-व्यापार से लेकर खेलों तक राज्य में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के मार्गदर्शन और नीति आयोग के निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक विभाग में सुशासन के मूल भाव के साथ गतिविधियों की मॉनिटरिंग जारी है। राज्य सरकार के हर विभाग ने अपने-अपने क्षेत्र में श्रेष्ठतम कार्य करने का संकल्प लिया है। राज्य सरकार कुशल वित्तीय प्रबंधन के आधार पर अपनी पुरानी देनदारी चुका कर, नई दृष्टि से विकास के पैमानों पर आगे बढ़ रही है।विकास के साथ औद्योगिक गतिविधियों और जन हितैषी कार्यों का विस्तार इन्हीं दृढ़संकल्पों की परिणीती है। राज्य सरकार, प्रदेशवासी और अधिकारी-कर्मचारी एकजुट होकर एक भावना के साथ प्रगति पर अग्रसर हों, इसी मंशा के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस वर्ष बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया, बावजूद इसके गत वर्ष की तुलना में बजट में 16 प्रतिशत की वृद्धि की गई। कुशल वित्तीय प्रबंधन और सभी के सहयोग से सरकार हर क्षेत्र में अपने तय लक्ष्यों को प्राप्त कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मीडिया को जारी संदेश में यह विचार व्यक्त किए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि राज्य सरकार ने शासकीय कर्मचारियों के हित में लगभग 10-15 वर्ष तक पुराने भत्तों की राशि बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके लिए वर्ष 2025-26 के बजट में राशि आवंटित की गई है, जिससे सरकार पर करीब 1500 करोड़ रुपए का व्यय भार आएगा।

40 साल बाद कोई भारतीय एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएगा

नई दिल्ली (एजेंसी)। इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला एक्सिओम मिशन 4 के तहत मई में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जा सकते हैं। इस मिशन में चार देशों के चार एस्ट्रोनॉट 14 दिन के लिए स्पेस स्टेशन जाने वाले हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने एक अपडेट में इसकी जानकारी दी। नासा और इसरो के बीच हुए एग्रीमेंट के तहत ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को इस मिशन के लिए चुना गया है। अभी वह इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर है। शुभांशु इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे। इससे पहले राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रा की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सीएम को फटकार लगाई

नई दिल्ली (एजेंसी)। तेलंगाना बीआरएस के 10 बागी विधायकों की अयोग्यता वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को उनके एक बयान पर फटकार लगाई।

सुप्रीम कोर्ट के जज संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करेंगे

नई दिल्ली(एजेंसी)। ज्यूडिशियरी में ट्रांसपेरेंसी और जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने पदभार ग्रहण करने के दौरान ही अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करने का फैसला किया है।

1 अप्रैल को हुई फुल कोर्ट मीटिंग में सभी 34 जजों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की मौजूदगी में अपनी संपत्ति का खुलासा करने का फैसला लिया है। जजों ने यह भी कहा कि संपत्तियों से जुड़ी डिटेल सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

वक्फ बिल पर राज्यसभा में चर्चा

नई दिल्ली (एजेंसी)। वक्फ संशोधन बिल बुधवार को लोकसभा में पास होने के बाद गुरुवार को राज्यसभा में पेश किया गया। दोपहर 1 बजे से चर्चा हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने वक्फ बिल पर विपक्ष के रुख को लेकर निशाना साधा। नड्डा ने कहा- हमने कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की तुलना में वक्फ बिल को लेकर कहीं ज्यादा गंभीरता दिखाई। यह बिल पार्टी इंट्रेस्ट का नहीं है, यह नेशनल इंट्रेस्ट का विषय है। इसलिए मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए। विषय को डिरेल नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा- बिल में कहीं राम मंदिर आ रहा है। कहीं कुंभ मेला दिख रहा है। बिहार का इलेक्शन दिख रहा। कहीं एअर इंडिया बिक गया। कहीं केरला का सिनेमा आ गया। ये सब चर्चा को डिरेल करने की कोशिश है। रिजिजू बोले- कानून में ट्रांसपैरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एक्यूरेसी

केंद्रित बदलाव अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि व्यापक चर्चा के बाद तैयार किए गए बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया था। वक्फ को लेकर जेपीसी ने जितना काम किया, उतना काम किसी कमेटी ने नहीं किया। इससे पहले बुधवार देर रात तक चर्चा के बाद इस बिल को लोकसभा से पारित कर दिया गया।

वक्फ बिल पर नीतीश ने भाजपा का साथ क्यों दिया

पटना (एजेंसी)। अपनी छवि और राजनीति को करीने से साधने वाले नीतीश कुमार ने चुनावी साल में बोल्ड डिसीजन लिया है, जो चर्चा का विषय बन गया है। अब तक जानकारों का मानना था कि चुनावों के मद्देनजर जेडीयू मुस्लिम वोटर्स को नाराज नहीं कर सकती, इसलिए वह ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ती, जहां उससे मुस्लिम वोटर्स को साधने की जरूरत महसूस होती है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव हैं। 2023 के जातीय गणना के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में 17.7त्न मुस्लिम हैं। जिनका राज्य के करीब 47 सीटों पर प्रभाव है। ऐसे में नीतीश कुमार ने वक्फ बिल पर मोदी का साथ दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो पार्टी अध्यक्ष ने अपने सांसदों को स्पष्ट संदेश दिया कि आप मुस्लिम वोटों की चिंता ना करें। बिल के मूल ड्राफ्ट में प्रावधान था कि नया कानून लागू होने के 6 महीने के अंदर एक सेंट्रल पोर्टल पर सभी वक्फ प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। 6 महीने बाद प्रॉपर्टी को लेकर कानून के तहत कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं की जा सकेगी। जेडीयू के सांसद दिलेश्वर कामत ने इस प्रावधान में संशोधन का सुझाव दिया था, जिसे जेपीसी ने स्वीकार कर लिया।

बंगाल में 25,753 शिक्षकों की बर्खास्तगी का आदेश बरकरार

नई दिल्ली (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में स्स्ट ने 2016 में 25 हजार शिक्षकों और गैर-शिक्षकों को नियुक्ति की थी। हाईकोर्ट ने इन नियुक्तियों को अवैध करार देते हुए कर्मचारियों को बर्खास्त किया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की जांच को सही माना और कहा कि पूरी प्रक्रिया में धोखाधड़ी की गई। इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने सुनवाई की। शीर्ष कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिकाएं

दायर की गई थीं। इसके साथ ही एसएससी जांच के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर 4 अप्रैल को सुनवाई करेगी। ममता बोलीं- व्यक्तिगत तौर पर फैसला स्वीकार नहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ देर बाद ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान आया। ममता ने कहा- वह व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार नहीं करती हैं, लेकिन उनकी सरकार इसे लागू करेगी और चयन प्रक्रिया को फिर से दोहराएगी। उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या विपक्षी भाजपा और सीपीएम चाहते हैं कि बंगाल की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाए। उन्होंने कहा, इस देश के नागरिक के रूप में, मेरे पास हर अधिकार है और मैं जजों के प्रति सम्मान के साथ इस फैसले को स्वीकार नहीं कर सकती।

मनरेगा घोटाला- शमी की बहनोई से वसूली होगी

अमरोहा (एजेंसी)। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बहन-बहनोई के मनरेगा मजदूरी मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। अमरोहा डीएम निधि गुप्ता ने 3 पंचायत सचिव समेत 8 अफसर-कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। डीएम ने तत्कालीन बीडीओ प्रतिभा अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को लेटर लिखा है। प्रधान का बैंक खाता ?सीज करा दिया है। गांव की प्रधान गुले आइशा, शमी की बहन शबीना की सास हैं। इधर, 3 सदस्यीय टीम ने दो दिन पहले डीएम को अपनी रिपोर्ट सौंपी। जिसमें पता चला कि बहन-बहनोई समेत 18 लोगों ने फर्जी मनरेगा कार्ड बनवाकर 8 लाख 68 हजार रुपए लिए। अब इन लोगों से पैसे की वसूली की जाएगी। डीएम ने स्नढ्ढक्रके आदेश भी दिए हैं।

25 मार्च को दैनिक भास्कर ने फर्जीवाड़े का खुलासा किया था। इसमें बताया गया था कि अमरोहा के पलौला गांव में मनरेगा में बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। यहां की करोड़पति ग्राम प्रधान गुले आयशा ने अपने परिवार के सभी सदस्यों, जानने वालों और चहेतों को मजदूर बना दिया था। इनके खाते में पैसे आए और निकाले भी गए।

दिल्ली-एनसीआर में 1 साल तक पटाखे बैन

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर में पटाखे बनाने, स्टोर करने और बेचने पर लगे प्रतिबंध को एक साल के लिए बढ़ा दिया। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा- वायु प्रदूषण का स्तर काफी समय से खतरनाक बना हुआ है। आबादी का एक बड़ा हिस्सा सड़कों पर काम करता है और प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित है। पीठ ने कहा कि हर कोई

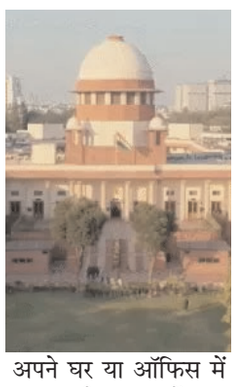

अपने घर या ऑफिस में एयर प्यूरीफायर नहीं लगा सकता। जब तक कोर्ट इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाता कि ग्रीन पटाखों से बहुत कम प्रदूषण होता है, तब तक पिछले आदेशों पर पुनर्विचार करने का सवाल ही नहीं उठता। सुनवाई के दौरान निजी रूप से पेश इंजीनियर मुकेश सिंह ने कहा कि पटाखे पर पाबंदी का फैसला ठीक नहीं है। पटाखे पर्यावरण साफ करते हैं। उन्होंने दलील दी कि पटाखे पर बैन अंतरराष्ट्रीय षडयंत्र का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर, 2024 को दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर साल भर के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था।

मुंबई में लॉरेंस गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार

मुंबई (एजेंसी)। मुंबई क्राइम ब्रांच ने अंधेरी इलाके से लॉरेंस गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 7 पिस्तौल और 21 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। पुलिस ने बुधवार, 2 अप्रैल को यह जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें संदेह है कि गैंग के निशाने पर कोई सेलिब्रिटी था। क्राइम ब्रांच के अधिकारी ने बताया कि विशेष सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने लॉरेंस गैंग के सदस्यों को शनिवार को हिरासत में लिया। उनके हथियार ले जाने के पीछे के मकसद की जांच की जा रही है गिरफ्तार लोगों की पहचान विकास ठाकुर उर्फ विक्की, सुमित कुमार दिलावर, श्रेयस यादव, देवेंद्र सक्सेना और विवेक गुप्ता के रूप में की गई है। ये सभी राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। सुमित कुमार और विकास हिस्ट्रीशीटर हैं। दरअसल, लॉरेंस गैंग की तरफ से सलमान खान को लगातार धमकियां मिल रही हैं।

मुंबई में लॉरेंस गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार

मुंबई (एजेंसी)। मुंबई क्राइम ब्रांच ने अंधेरी इलाके से लॉरेंस गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 7 पिस्तौल और 21 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। पुलिस ने बुधवार, 2 अप्रैल को यह जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें संदेह है कि गैंग के निशाने पर कोई सेलिब्रिटी था। क्राइम ब्रांच के अधिकारी ने बताया कि विशेष सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने लॉरेंस गैंग के सदस्यों को

शनिवार को हिरासत में लिया। उनके हथियार ले जाने के पीछे के मकसद की जांच की जा रही है।

गिरफ्तार लोगों की पहचान विकास ठाकुर उर्फ विक्की, सुमित कुमार दिलावर, श्रेयस यादव, देवेंद्र सक्सेना और विवेक गुप्ता के रूप में की गई है। ये सभी राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। सुमित कुमार और विकास हिस्ट्रीशीटर हैं।

योगी के दौरे से पहले अफसरों ने 20-बीघा फसल कटवाई

वाराणसी (एजेंसी)। वाराणसी में सीएम योगी ने आज पीएम मोदी के जनसभा स्थल का निरीक्षण किया। 48 घंटे पहले इस जगह पर 20 बीघा फसल खड़ी थी। सीएम का दौरा फाइनल होते ही अफसरों के हाथ-पांव फूल गए।

आनन-फानन में अधिकारियों ने पंचायत और तहसील के करीब 30 कर्मचारियों को फसल काटने में लगा दिया। 48 घंटे में फसल काटकर दाना-भूसा किसानों के घर पहुंचा दिया। इसके बदले एक भी रुपया नहीं लिया। अब खेत समतल हो चुका है और हैलीपैड भी बनकर तैयार है। काशी में 11-12 अप्रैल को पीएम मोदी की रैली होने वाली है। इसके लिए मेहंदीगंज गांव को चुना गया है। जनसभा स्थल किसान उधवेंदु पांडेय के 16 बीघा खेत में बन रहा है, जबकि सुरेंद्र यादव के 4 बीघा खेत में हेलीपैड बनकर तैयार हो गया है। मंगलवार को प्रशासनिक अफसर गांव पहुंचे और दोनों किसानों से बात की।

सोनिया गांधी ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर कहा- देश को रसातल पर ले जा रही सरकार, बिल जबरन पारित किया

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी (सीपीपी) की बैठक में कहा कि लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को केंद्र सरकार ने जबरन पारित करवाया है। यह विधेयक संविधान पर हमला है और हमारे समाज को स्थायी रूप से तोड़ने की बीजेपी की सोची-समझी रणनीति का एक हिस्सा है। इस अवसर पर सोनिया गांधी ने उपस्थित कांग्रेस सांसदों से कहा, कि मोदी सरकार देश को रसातल में ले जाने का काम कर रही है। वह संविधान पर हमला कर उसे ध्वस्त करना चाहती है। इस तरह से तो संविधान महज कागजों में रह जाएगा। वन नेशन-वन इलेक्शन बिल भी

संविधान का उल्लंघन है, जिसका हम विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सांसद मोदी सरकार की भारत को निगरानी राज्य में बदलने की मंशा को उजागर करने का काम करें।

बहुचर्चित वक्फ संशोधन बिल सोमवार देर रात लोकसभा में पारित हो गया, जिससे भारतीय राजनीति में हलचल मच गई है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को इस बिल पर तीखा प्रहार करते हुए इसे समाज को बांटने वाला और संविधान को कमजोर करने वाला करार दिया। कांग्रेस संसदीय समिति को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए और कहा, भाजपा ने इस बिल को लोकसभा में बुलडोजर से पारित किया है।

सोनिया गांधी ने लोकसभा में बहस के दौरान विपक्षी सांसदों को अपनी बात रखने का मौका न मिलने की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, यह बेहद चिंताजनक है कि विपक्षी सांसदों को अपनी बात कहने नहीं दी जाती। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को भी अपनी बात रखने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

राहुल बोले-चीन ने हमारी 4 हजार वर्ग किमी जमीन कब्जाई

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को भारत-चीन के राजनयिक संबंधों की 75वीं सालगिरह के जश्न को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा- चीन हमारे 4 हजार वर्ग किमी इलाके पर कब्जा करके बैठा है, लेकिन मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि हमारे विदेश सचिव (विक्रम मिस्री) चीनी राजदूत के साथ केक काट रहे थे। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान राहुल ने कहा- हम सामान्य स्थिति के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपनी जमीन वापस मिलनी चाहिए। मुझे पता चला कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने चीनी राजदूत को चिट्ठी लिखी है और यह भी हमें दूसरों से पता चल रहा है। चीनी राजदूत भारत के लोगों को बता रहे हैं कि उन्हें चिट्ठी लिखी गई। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बीती 1 अप्रैल को भारत-चीन संबंधों के 75 साल पूरे होने पर भारत में आयोजित एक

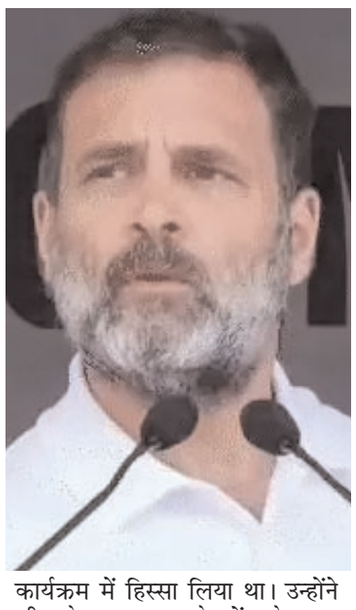

कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। उन्होंने चीन के राजदूत शू फेइहोंग के साथ काटा था। फेइहोंग ने एक्स पर कार्यक्रम की तस्वीरें शेयर की थीं। राहुल बोले- भाजपा की फिलॉस्फी हर विदेशी के सामने सिर झुकाना मोदी सरकार की विदेश नीति पर राहुल गांधी ने कहा- एक तरफ आपने चीन को हमारी जमीन दे दी और दूसरी तरफ अमेरिका ने हम पर टैरिफ (जैसे को तैसा टैक्स) लगा दिया। इससे देश की ऑटो, फार्मास्यूटिकल और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। राहुल ने कहा- एक बार किसी ने इंदिरा जी से पूछा कि विदेश नीति के मामले में आप बाएं झुकती हैं या दाएं। इस पर उन्होंने जवाब दिया की मैं बाएं या दाएं नहीं झुकती। मैं भारतीय हूं और सीधी खड़ी हूं।

भाजपा और आरएसएस की फिलॉस्फी अलग है। जब उनसे पूछा जाता है तो वे कहते हैं नहीं, नहीं, हम हर विदेशी के सामने अपना सिर झुकाते हैं। यह उनके इतिहास में है, हम जानते हैं। सरकार को जवाब देना चाहिए कि वह अमेरिकी टैरिफ पर क्या कर रही है। बीते दिन अमेरिका ने भारत पर 26 प्रतिशत रेसिप्रोकल टैरिफ (जैसे को तैसा टैक्स) लगाने की घोषणा की है। अमेरिका ने कहा है कि भारत अमेरिकी सामानों पर बहुत ज्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी (आयात शुल्क) लगाता है। राहुल गांधी ने 2022 में लद्दाख दौरे पर कारगिल में रैली की थी। वहां उन्होंने दावा किया था कि चीन ने भारत की हजारों किमी जमीन पर कब्जा किया है। इस पर लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर (रिटायर्ड) बीडी मिश्रा ने कहा था कि चीन का भारत की एक वर्ग इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं है। उन्होंने कहा था- 1962 (भारत-चीन युद्ध) में जो कुछ भी हुआ, उस पर बात करने से कोई फायदा नहीं। आज सीमा की आखिरी इंच जमीन भी हमारे कब्जे में है। भगवान न करे अगर हालात बिगड़े तो सेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है।

यशस्वी की नेटवर्थ तेजी से बढ़ रही

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय टीम के युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल आजकल आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स से खेल रहे हैं। यशस्वी ने भारतीय टीम के अवसर मिलने के बाद लगातार अच्छे प्रदर्शन से टीम में जगह पक्की की है हालांकि उनका यहां तक का सफर आसान नहीं रहा है। यशस्वी क्रिकेटर बनने बचपन में ही उत्तरप्रदेश के शहर भदोही से निकलकर मुंबई पहुंचे थे। यहां यशस्वी को आजाद मैदान में कई रातें टेंट में गुजारनी पड़ी थी।

ऐसा भी समय आया जब खाना भी उन्हें बड़ी मुश्किल से मिला हालांकि खेल के बल पर आज उनकी कमाई करोड़ों में पहुंच गयी है। उनकी नेटवर्थ में लगातार बढ़ती जा रही है। वह क्रिकेट के अलावा विज्ञापनों से भी काफी कमाई कर रहे हैं। यशस्वी को राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2025 ऑक्शन में 18 करोड़ में बरकरार रखा था। इससे उनकी कुल संपत्ति तेजी से बढ़ी है। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 में यशस्वी की नेटवर्थ तकरीबन 16 करोड़ थी। आईपीएल 2025 ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें अठारह करोड़ में बरकरार रखा.जिससे उनकी कुल संपत्ति और बढ़ गयी। वहीं साल 2022 में में उनकी नेटवर्थ लगभग 12 करोड़ थी। साल 2020 में उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 2 करोड़ 40 लाख रुपये में खरीदा था। 2021 में भी इस फ्रेंचाइजी ने इसी अनुबंध के साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया लेकिन साल 2022 में राजस्थान ने उन्हें 4 करोड़ में अपने साथ बरकरार रखा था।

यशस्वी ने बताया मुम्बई छोड़कर गोवा जाने का कारण

मुम्बई (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट टीम के युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल अब घरेलू सत्र में मुम्बई की जगह गोवा से खेलते हुए नजर आयेंगे। यशस्वी के अचानक ही गोवा का रुख करने से सभी हैरान है पर अब इसका कारण सामने आया है। यशस्वी ने कहा कि ये फैसला काफी कठिन था पर कप्तानी का प्रस्ताव मिलने के कारण उन्होंने ये फैसला किया है पर इसके बाद भी वह हमेशा मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) के आभारी रहेंगे।वहीं इससे पहले यशस्वी ने आगामी घरेलू सत्र में गोवा का प्रतिनिधित्व करने के लिए एमसीए से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) मांगा था। यशस्वी ने कहा कि उन्होंने शुरुआत से ही मुम्बई की ओर से खेला था इसलिए ये फैसला करना उनके लिए कठिन था। साथ ही कहा कि मैं आज जो कुछ भी हूं, वह मुंबई की वजह से हूं।

इस शहर ने ही मुझे यहां तक पहुंचाया है। इसलिए में हमेशा ही एमसीए का आभारती रहूंगा हालांकि गोवा ने मुझे एक नया अवसर दिया है और जिसमें मुझे कप्तानी का अवसर मिला है। मेरा पहला लक्ष्य भारतीय टीम की ओर से अच्छा प्रदर्शन करना होगा और जब भी मैं राष्ट्रीय टीम में नहीं रहूंगा, मैं गोवा के लिए खेलूंगा और उन्हें टूर्नामेंट में आगे ले जाने की कोशिश करूंगा। यह एक अहम मौका था, जो मेरे पास आया और मैंने इसे स्वीकार कर लिया.' इस क्रिकेट ने अंतिम बार मुंबई के लिए जम्मू और कश्मीर के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में खेला था, जहां उन्होंने रोहित के साथ पारी शुरु की थी।

महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया ने लिया संन्यास, ओलंपिक में भारत के लिए लगाई थी हैट्रिक

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय महिला हॉकी टीम की दिग्गज खिलाड़ी वंदना कटारिया ने मंगलवार को संन्यास का ऐलान किया। वंदना ने भारत के लिए 300 से ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेले हैं। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हैट्रिक लगाई थी, जिसके बाद वह ऐसा करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी थी। वंदना हरिद्वारा के रोशनाबाद की रहने वाली हैं। वह अपने खेल से तब से चर्चा में है जब उन्होंने जूनियर वर्ल्ड कप 2013 में बेहतरीन खेल दिखाया। उन्होंने वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा पांच गोल किए थे। भारत ने जूनियर वर्ल्ड कप 2013 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इस प्रदर्शन के बाद उन्हें भारतीय महिला हॉकी टीम में खेलने का मौका मिला। भारत के लिए खेलते हुए उन्होंने 2014 एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके बाद 2018 एशियन गेम्स में सिल्वर और 2023 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वंदना ने कप्तान के तौर पर भारत को एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2016 में गोल्ड मेडल जिताया था। वहीं 2018 में सिल्वर पर कब्जा जमाया था। जिसके बाद उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी दिया गया। 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में चौथे स्थान पर फिनिश किया था। वंदना ने इसमें बहुत अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद वंदना को भारतीय हॉकी में दिए गए योगदानों और बेहतरीन खेल के लिए कई अवॉर्ड्स से सम्मानित भी किया गया। इस दौरान 2021 में अर्जुन अवॉर्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। इसके बाद उन्हें 2022 में पद्म श्री भी दिया गया।

स्टोक्स के चोटिल होने से इंग्लैड टीम को लगा झटका

लंदन (एजेंसी)। इंग्लैड टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स चोटिल हो गये है। इससे इंग्लैड की टीम को करारा झटका लगा है क्योंकि उसे भारत के खिलाफ जून में टेस्ट सीरीज खेलनी है जिसके लिए उसे तैयारी करनी है। स्टोक्स हैमस्ट्रिंग की इस चोट के कारण डरहम के काउंटी चैंपियनशिप से बाहर हो गए है है। वह हालांकि हैमस्ट्रिंग सर्जरी से उबर रहे हैं। मुख्य कोच रयान कैंपबेल को हालांकि भरोसा है कि वह भारतीय टीम के दौरे तक उबर जाएंगे। स्टोक्स छह महीने में दूसरी बार हैमस्ट्रिंग से जूझ रहे हैं। इससे पहले न्यूजीलैंड में इंग्लैंड के अंतिम टेस्ट के दौरान भी वह चोटिल हो गए थे, तब से लेकर स्टोक्स ने कोई मैच नहीं खेला है। एक रिपोर्ट के अनुसार स्टोक्स शुक्रवार से शुरू हो रही काउंटी चैंपियनशिप में नहीं खेल पायेंगे। उनके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने के बाद डरहम और इंग्लैंड के उनके साथी खिलाड़ी ब्रायडन कार्से भी नहीं खेलेंगे।

बार्सिलोना और रियाल मैड्रिड में होगा खिताबी मुकाबला

नई दिल्ली (एजेंसी)। बार्सिलोना ने बुधवार को यहां एटलेटिको मैड्रिड को सेमीफाइनल के दूसरे चरण में 1-0 से हराकर कोपा डेल रे फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया जहां उसका सामना अपने चिर प्रतिद्वंद्वी रियाल मैड्रिड से होगा। बार्सिलोना की तरफ से फेरान टोरेस ने पहले हाफ में गोल किया जो आखिर में निर्णायक साबित हुआ। इससे पहले इन दोनों टीमों के बीच फरवरी में खेला गया सेमीफाइनल का पहला चरण 4-4 से बराबर रहा था।

इस तरह से बार्सिलोना ने कुल मिलाकर 5-4 से जीत दर्ज करकेफाइनल में जगह बनाई। यह पिछले चार सत्र में पहला अवसर है जबकि बार्सिलोना इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा है।

रियाल मैड्रिड ने मंगलवार को अतिरिक्त समय तक चले मैच में रियाल सोसिदाद को 5-4 के कुल स्कोर से पराजित करके फाइनल में जगह बनाई थी। इन दोनों टीमों के बीच 2013-14 सत्र के बाद पहली बार फाइनल खेला जाएगा। तबरियाल मैड्रिड ने खिताब जीता था।

बुमराह की वापसी को लेकर संशय बरकरार

मुम्बई (एजेंसी)। भारतीय टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की खेल में वापसी को लेकर संशय बना हुआ है। बुमराह चोटिल होने के कारण ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद से ही टीम से बाहर हैं। इसी कारण वह चैम्पियंस ट्रॉफी भी नहीं खेल पाये। अब उनके इंग्लैंड के खिलाफ जून में होने वाली टेस्ट सीरीज से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की संभावनाएं हैं। फिट नहीं होने के कारण ही वह आईपीएल से भी बाहर हैं। उनके अप्रैल के पहले सप्ताह तक पूरी तरह ठीक होने की उम्मीद थी पर अब इसकी संभावना नहीं हैं। ऐसे में उनके प्रशंसकों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) की मेडिकल टीम उनकी वापसी को लेकर किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करना चाहती। मेडिकल टीम नहीं चाहती कि मैदान पर वापसी के बाद उनके फिर चोटिल होने का खतरा हो। वहीं सकारात्मक बात ये है कि बुमराह ने नेट पर गेंदबाजी शुरू कर दी है पर अभी वह पूरी ताकत और क्षमता से गेंद नहीं फेंक रहे हैं। सेंटर ऑफ एक्सिलेंस में बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी निगरानी कर रही है। टीम उनकी क्रिकेट के मैदान पर वापसी को लेकर किसी भी तरह की जल्दबाजी के पक्ष में नहीं है क्योंकि इसमें जोखिम हो सकता है। इससे वह स्ट्रेस फैक्टर का शिकार हो सकते हैं। मेडिकल टीम का मानना है कि बुमराह को 100 प्रतिशत फिट होने पर ही वापसी करनी चाहिये। वहीं एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार बुमराह की चोट थोड़ी ज्यादा गंभीर है। मेडिकल टीम ये पक्का करना चाहती है कि वह फिर स्ट्रेस फैक्टर का शिकार न हों। बुमराह स्वयं भी इस मामले में सावधानी रख रहे हैं।

ईशान को इस बार भी बीसीसीआई अनुबंध मिलने की संभावना नहीं

मुम्बई (एजेंसी)। पिछले काफी समय से भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे ईशान किशन आजकल आईपीएल खेल रहे हैं। ईशान का इसमें अब तक का प्रदर्शन मिलाजुला रहा है। पहले ही मैच में उन्होंने शतक लगाया था पर बाद के मैचों में वह रन नहीं बना पाये। वहीं भारतीय क्रिकेट बोर्ड आने समय में केन्द्रीय अनुबंध देने जा रहा है।

इसमें इस बार भी ईशान को अवसर मिलने की संभावना नहीं है। ईशान को घरेलू क्रिकेट नहीं खेलने के कारण पिछले बार भी अनुबंध नहीं मिला था। ईशान केअलावा श्रेयस अय्यर को भी पिछले साल अनुबंध नहीं मिला था पर इस बार जहां श्रेयस की वापसी तय है, वहीं ईशान को अभी इंतजार करना होगा। श्रेयस ने बीसीसीआई की फटकार के बाद घरेलू क्रिकेट खेल लिया था और इससे उनकी भारतीय टीम में भी वापसी हो गयी थी। अभी श्रेयस आईपीएल में भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बीसीसीआई अनुबंध सूची अभी जारी नहीं हुई है पर कहा जा रहा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को इसमें ए प्लस में ही बनाये रखा जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार बीसीसीआई श्रेयस को अपना अनुबंध वापस दे सकती है।

आरसीबी की हार का कारण बने उसके ही पुराने गेंदबाज सिराज

बेंगलुरु (एजेंसी)। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के शानदार प्रदर्शन से गुजरात टाइटंस ने आईपीएल के 18 वें सत्र में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) को 8 विकेट से हरा दिया। सिराज पिछले सत्र में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की टीम में शामिल थे पर इस बार वह गुजरात की ओर से खेल रहे हैं। ऐसे में उन्हें इस बार रिटेन न कर आरसीबी पछता रही होगी। इस मैच में सिराज के सामने आरसीबी के गेंदबाज टिक नहीं पाये।

सिराज ने बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी की और आरसीबी के 3 बड़ विकेट लिए। उन्होंने 4 ओवर में केवल 19 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। इसी कारण उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। वहीं पिछले सत्र में जब गुजरात और आरसीबी का पहला मुकाबला हुआ था तब भी सिराज ही प्लेयर ऑफ द मैच थे पर उस समय वह गुजरात की ओर से खेल रहे थे। आरसीबी ने इस बार सिराज को रिलीज कर दिया था। इसके बाद हुई नीलामी में टाइटंस ने उन्हें 12.5 करोड़ की बोली लगाकर उन्हें खरीदा था। इस बार मैच में आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 169 रन बनाए। वहीं गुजरात ने जोस बटलर और साई सुदर्शन की विस्फोटक पारियों की सहायता से 18वें ओर में ही 8 विकेट से मैच जीत लिया। बटलर ने 39 गेंद में 73 जबकि सुदर्शन ने 36 गेंद में 49 रन बनाये। इस मैच में जीत से गुजरात के 4 अंक हो गए और वह चौथे नंबर पर पहुंच गयी है जबकि हार के बाद आरसीबी पहले से तीसरे नंबर पर फिसल गयी है।

अलग-अलग क्षेत्रों में छाये हैं ये पूर्व क्रिकेटर

मुम्बई (एजेंसी)। साल 2011 में महेन्द सिंह धोनी की कप्तानी में एकदिवसीय विश्वकप जीतने वाली भारतीय टीम के खिलाड़ी आजकल अलग-अलग क्षेत्रों में सक्रिय है। कोई कोच का काम रहा है तो कोई कमेंटेटर वहीं कुछ राजनेता भी बने हैं। तब भारतीय टीम में वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर, युवराज सिंह, सुरेश रैना और हरभजन सिंह सहित कई अन्य दिगग्ज भी शामिल थे। गौतम गंभीर और हरभजन सिंह संन्यास से लेने के बाद राजनीति में उतरे हैं। गंभीर ने साल 2019 के आम चुनाव में भाजपा के टिकट पर दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ा था और संसद बने थे। मगर इसके बाद एक बार फिर वह राजनीति से संन्यास लेकर वह भारतीय टीम के मुख्य कोच की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हरभजन सिंह आम आदमी पार्टी की टिकट से राज्यसभा सांसद हैं। इसके साथ ही वह क्रिकेट कमेंट्री भी करते हैं। खेल से संन्यास के बाद कोचिंग करने वालों में सहवाग का भी नाम आता है। वह भारतीय टीम के कोच बनना चाहते थे पर सफल नहीं हुए। वह आईपीएल में पंजाब किंग्स की के कोच रहे थे। वह अपनी क्रिकेट अकादमी भी चलाते हैं।

हालांकि अब वह आईपीएल में कमेंट्री करते हैं। वहीं सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह अपने-अपने एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं। इसके जरिये वह समाज सेवा और दूसरे जनहित के काम करते हैं। ये दोनो ही रिटायर्ड खिलाड़ियों की लीग में भी खेलते हैं। महेन्द्र सिहं धोनी आईपीएल खेलने के साथ ही खेती भी करते हैं और कई प्रकार के कारोबारों से जुड़े हैं।

स्टोक्स के चोटिल होने से इंग्लैड टीम को लगा झटका

लंदन (एजेंसी)। इंग्लैड टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स चोटिल हो गये है। इससे इंग्लैड की टीम को करारा झटका लगा है क्योंकि उसे भारत के खिलाफ जून में टेस्ट सीरीज खेलनी है जिसके लिए उसे तैयारी करनी है। स्टोक्स हैमस्ट्रिंग की इस चोट के कारण डरहम के काउंटी चैंपियनशिप से बाहर हो गए है है। वह हालांकि हैमस्ट्रिंग सर्जरी से उबर रहे हैं। मुख्य कोच रयान कैंपबेल को हालांकि भरोसा है कि वह भारतीय टीम के दौरे तक उबर जाएंगे। स्टोक्स छह महीने में दूसरी बार हैमस्ट्रिंग से जूझ रहे हैं। इससे पहले न्यूजीलैंड में इंग्लैंड के अंतिम टेस्ट के दौरान भी वह चोटिल हो गए थे, तब से लेकर स्टोक्स ने कोई मैच नहीं खेला है। एक रिपोर्ट के अनुसार स्टोक्स शुक्रवार से शुरू हो रही काउंटी चैंपियनशिप में नहीं खेल पायेंगे। उनके अलावा

चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने के बाद डरहम और इंग्लैंड के उनके साथी खिलाड़ी ब्रायडन कार्से भी नहीं खेलेंगे। वह भी पैर की अंगुली की चोट से उबर रहे हैं जिसके कारण वह भी पिछले महीने चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए थे।

मुख्य कोच ने कहा, 'वे फिलहाल गंभीर चोटों से उबर रहे हैं। हालांकि उन्हें टेस्ट मैचों के शुरू होने से पहले अपने आप को फिट रखना होगा। इंग्लैंड को 22 मई को ट्रेंट ब्रिज में जिम्बाब्वे के खिलाफ शुरू होगा, उसके बाद भारत के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज होगी। ऑस्ट्रेलिया के एशेज दौरे के देखते हुए स्टोक्स आठ महीनों में 11 टेस्ट को खेलने के लिए अपनी वापसी को जरुरी मानते हैं। ऑलराउंडर स्टोक्स ने डरहम में अपनी रिकवरी जारी रखते हुए फिर से प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। दस दिन पहले ही उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट को साझा किया था जिसमें वह नेट् अभ्यास में गेंदबाजी करते दिख रहे थे।

प्रायवेट स्कूलों की मनमाना वसूली में शिकंजा कसने नाकाम जिला प्रशासन

पहली कक्षा से नीचे की पढ़ाई पर सालाना एक लाख रुपये का शुल्क, प्रवेश शुल्क के नाम डाल रहे डाका

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। अगली कक्षा में प्रवेश के नाम पर प्राइवेट विद्यालयों में प्रवेश शुल्क की वसूली पर भले ही सरकार ने रोक लगा दी हो लेकिन सरकार का यह आदेश पूरी तरह से बेअसर साबित हो रहा है। पूर्व की भांति अगली कक्षा में प्रवेश के नाम पर प्राइवेट विद्यालयों में प्रवेश-शुल्क के नाम पर लूट मची हुई है। जबकि प्रदेश सरकार ने विद्यालयों में छात्रों के प्रवेश को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिसके तहत किसी भी निजी विद्यालय में प्रवेश शुल्क मात्र एक बार ही लिया जा सकता है। उसके बाद अगली कक्षा में प्रवेश के दौरान विद्यालय तंत्र द्वारा कोई प्रवेश शुल्क वसूल करने पर सरकार द्वारा पाबंदी लगा दी गई है।

इतना ही नहीं सरकार ने विद्यालय तंत्र द्वारा बिक्री किए जा रहे पाठ्य पुस्तकों व स्कूली ड्रेस आदि सामानों की बिक्री पर भी पाबंदी लगा दी है। लेकिन सरकार का यह आदेश हवा-हवाई साबित हो रहा है। हालत यह है कि अधिकांश

प्राइवेट विद्यालय में अगली कक्षा में प्रवेश के दौरान मोटी धनराशि और प्रवेश शुल्क वसूल की जा रही है। वहीं प्रथम बाद प्रवेश के लिए तो विद्यालय संचालक लाखों की रकम वसूलने में कमी नहीं कर रहे हैं। साथ ही भारी-भरकम धनराशि वसूल कर विद्यालय से ही बच्चों को पाठ्य पुस्तकों के साथ स्कूली ड्रेस भी मुहैया कराया जा रहा है। अभिभावकों ने बताया कि अगली कक्षा में प्रवेश कराने के दौरान विद्यालय तंत्र द्वारा प्रवेश शुल्क के नाम पर भी मोटी रकम वसूल की जा रही है। प्रवेश शुल्क के नाम पर निजी स्कूलों द्वारा जहां मोटी धनराशि एक मुश्त वसूल की जा रही है तो वही मासिक शिक्षण शुल्क के नाम पर भी मोटी रकम जमा करने का फरमान विद्यालय तंत्र द्वारा सुनाया जा रहा है।

शिक्षा विभाग की लापरवाही से हो रहा अभिभावकों का शोषण: बताया जा रहा है कि सीबीएसई के दिशानिर्देश अनुसार निजी स्कूल केवल उन्हीं मदों पर फीस ले सकते हैं जो शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित हों। लेकिन विभाग ने ऐसी कोई सूची जारी ही नहीं की है जिसका फायदा उठाकर स्कूल मनमाने मदों पर फीस वसूलते हैं जिससे लगातार अभिभावकों का शोषण हो रहा है।

सीबीएसई के फीस को लेकर जारी दिशा-निर्देश

सीबीएसई की वेबसाइट पर उपलब्ध दस्तावेज में उल्लिखित है कि फीस शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित मदों के अनुसार ली जाएगी। परंतु रीवा जिला शिक्षा विभाग ने ऐसे मद निर्धारित नहीं किए हैं जिनके आधार पर निजी स्कूल फीस ले सकें और परिजनों को पता रहे कि उनसे जायज फीस ली जा रही है या नहीं। प्रवेश या किसी भी मद के अंतर्गत कोई भी फीस सरकार के प्रावधानों के अनुसार ही ली जा सकती है। आपको बता दें निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूलने पर सीबीएसई ने पूर्व में स्कूलों को सरकार के नियम, कानून का पालन करने के आदेश दिए थे परंतु फीस की समस्याओं को लेकर अभिभावकों को अब भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं।

मानस भवन में चार और पाँच अप्रैल को लगेगा पुस्तक मेला

पुस्तक मेले में 10 प्रतिशत छूट पर मिलेंगी किताबें

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। विद्यार्थियों को रियायती दर पर किताबें और स्कूल ड्रेस उपलब्ध कराने के लिए रीवा में मानस भवन में दो दिवसीय पुस्तक मेला लगाया जा रहा है। पुस्तक मेला चार और पाँच अप्रैल को सबुह 10 बजे से रात 10 बजे तक आयोजित होगा। प्रत्येक दुकानदार का पंजीयन करके स्टाल संख्या आवंटित की गई है। मेले में खरीददारों और वेंडर्स के लिए समुचित व्यवस्थाएं हैं। पुस्तक मेले में 10 प्रतिशत छूट पर किताबें मिलेंगी। पुलिस अधिकारी वाहनों की पार्किंग तथा भीड़ प्रबंधन के लिए उचित प्रबंध करेंगे तथा आयुक्त नगर निगम मेला स्थल में पेयजल और साफ-सफाई की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करायेंगे।

कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मेला स्थल का निरीक्षण करके सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएं। मेले में किताबों और स्कूल ड्रेस के सभी विक्रेता अपना स्टाल लगाएं, इसे सुनिश्चित करें। जिला शिक्षा अधिकारी मेले के प्रत्येक काउंटर पर कर्मचारी तैनात करें। मेले में सभी कक्षाओं की पूरी किताबों की बिक्री सुनिश्चित करें जिससे अभिभावक को किताबों के लिए पुनः दुकान न जाना पड़े। मेला स्थल में हेल्पडेस्क भी स्थापित करें। इसमें प्राप्त सूचनाओं तथा उन पर की गई कार्यवाही से प्रतिदिन सीईओ जिला पंचायत को अवगत कराएं। फीस बढ़ाने के संबंध में यदि कोई स्कूल संचालक शासन के निर्देशों का उल्लंघन करता पाया जाएगा तो उस पर दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

एक वर्ष से अधिक समय से लंबित सभी प्रकरण निराकृत करें

नियमित सुनवाई करने के निर्देश

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने राजस्व कार्यों की समीक्षा की। कलेक्टर ने नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, नक्शा तरमीम तथा सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की तहसीलवार समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि राजस्व अधिकारी एक वर्ष से अधिक सभी प्रकरणों की नियमित सुनवाई करके उनका इस माह निराकरण सुनिश्चित करें। लंबित प्रकरणों में समय सीमा में प्रतिवेदन दर्ज कराएं। समाधान ऑनलाइन के एजेण्डा बिन्दुओं में लंबित राजस्व प्रकरणों का विशेष प्रयास करके सात दिवस में निराकरण करें। सीएम हेल्पलाइन में भी 50 दिन से अधिक शिकायतों का तीन दिन में निराकरण न होने पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। सभी राजस्व अधिकारी विभागीय कार्यो के साथ-साथ अपने क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने पर भी विशेष ध्यान दें। त्यौहारों के दौरान कानून व्यवस्था की कड़ी निगरानी करें।

कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों को तहसीलदार स्वयं पढ़कर उनमें तथ्यपरक प्रतिवेदन दर्ज करें। सीमांकन, बंटवारा, नामांतरण तथा प्राकृतिक आपदा में राहत राशि के प्रकरण तय समय सीमा में निराकृत करें। समय सीमा के प्रकरण निराकृत न होने पर संबंधित अधिकारियों पर अर्थदण्ड लगाएं। सभी एसडीएम जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत बनाए जा रहे अमृत सरोवरों को खसरे में दर्ज कराएं। जल संसाधन विभाग की सभी नहरों को भी खसरे में अनिवार्य रूप से दर्ज करें। उचित मूल्य दुकानों का नियमित रूप से निरीक्षण करके खाद्यान्न का वितरण कराने के साथ-साथ 30 अप्रैल तक सभी राशन कार्डधारियों की ई केवाईसी अनिवार्य रूप से कराएं। इसमें लापरवाही बरतने वाले सेल्समैनों तथा सहायक आपूर्ति अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करें। ई केवाईसी न कराने पर 15 अप्रैल के बाद खाद्यान्न प्राप्त नहीं होगा। एसडीएम 15 अप्रैल तक ई केवाईसी न कराने वाले राशन कार्डधारियों का नाम पृथक करने की कार्यवाही करें। स्वामित्व योजना के तहत आरओआर सर्वे तथा ग्राउण्ड ट्रुथिंग का कार्य समय पर पूरा कराएं। पात्र हितग्राहियों को भू अधिकार पत्रों का समारोहपूर्वक वितरण कराएं। सभी वक्फ सम्पत्तियों का चिन्हांकन कर लिया गया है। इनका सत्यापन करके पोर्टल पर जानकारी दर्ज करें। प्राकृतिक आपदा में राहत राशि जारी करने के संबंध में शासन द्वारा मदवार निर्धारण कर दिया गया है। नये निर्देशों के अनुरूप राहत राशि के लंबित सभी प्रकरण सात दिवस में निराकृत करें।

बैठक में कलेक्टर ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि में ई केवाईसी अपडेशन तथा फार्मर रजिस्ट्री का कार्य भी प्राथमिकता से कराएं। पटवारियों की ड्यूटी लगाकर निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार ई केवाईसी अपडेट कराएं। गेंहू उपार्जन के लिए पंजीकृत सभी किसानों के रकबे का अनिवार्य रूप से सत्यापन करें। सभी राजस्व अधिकारी अपने क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था तथा विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों पर भी निगरानी रखें।

प्राकृतिक आपदा की सूचना मिलने पर तत्परता से कार्यवाही करें। बैठक में कलेक्टर ने धारणाधिकार योजना, ऑडिट कंडिकाओं के निराकरण, न्यायालय में लंबित प्रकरणों में जवाब दावा दायर करने, जल गंगा संवर्धन अभियान तथा गेंहू उपार्जन के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में आयुक्त नगर निगम डॉ सौरभ सोनवड़े, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर, अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी, संयुक्त कलेक्टर पीके पाण्डेय, संयुक्त कलेक्टर श्रेयस गोखले, सभी एसडीएम, जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सभी तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

इलेक्ट्रॉनिक दुकान और गोदाम में चोरों का धावा, लग्जरी वाहन से चोर

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। रीवा में चोरी की एक बड़ी वारदात हुई है। यहां लग्जरी कार सहित तीन अलग अलग वाहनों में पहुंचे अज्ञात चोरों ने इलेक्ट्रॉनिक दुकान में धावा बोला। चोरों ने दो दुकानों का ताला तोड़कर चोरी की वारदात की और सबूत मिटाने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी निकालकर ले गए। वहीं घटना के दौरान स्थानीय लोगों द्वारा शोर मचाने पर बदमाश भागने की जल्दबाजी में अपनी कार छोड़ गए, जिसे पुलिस ने जप्त कर लिया है। दरअसल यह घटना बीती रात शहर के रतहरा रिंग रोड में स्थित स्वास्तिक इलेक्ट्रॉनिक दुकान और गोदाम में हुई है। घटना के संबंध में दुकान संचालक पंकज पटेल ने बताया कि बीती रात अज्ञात चोरों ने उसकी दुकान और गोदाम में ताला तोड़कर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित की माने तो चोर एक लग्जरी कार सहित बुलेरो और पिकअप वाहन में आये थे, जिन्होंने वारदात को अंजाम देने से पहले दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को निकाल दिया, जिसके बाद कीमती इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर जाने लगे तभी स्थानीय लोगों को इसकी भनक लगी और उन्होंने शोर मचाया। हालांकि बदमाश सामान लेकर भागने में कामयाब रहे। गुरुवार सुबह पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल के समीप खड़ी चोरों की कार को जप्त कर लिया है, कार यूपी नंबर की बताई जा रही है। दुकान से करीब दो से ढाई लाख का माल चोरों ने पार कर दिया है।

खुद को बेटे का दोस्त बताकर घर में घुसे तीन डकैतों ने बुजुर्ग को 3 घंटे बंधक बनाए रखा

गन प्वाइंट पर 30 लाख की लूट, सोना और कैश लेकर हुये फरार

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। खुद को बेटे का दोस्त बताकर घर में घुसे तीन डकैतों ने बुजुर्ग को 3 घंटे बंधक बनाए रखा। उनके मोबाइल का सिम तोड़ा, पिस्तौल दिखाकर 20 तोला सोना और 2 लाख रुपए का कैश लूट लिया। इस बीच जब बुजुर्ग डरा तो उसे दवा भी खिलाई, बेटे का ऑनलाइन ऑर्डर आया तो वह देने आए व्यक्ति से भी खुद ही सामान ले लिया। आरोपियों ने बुजुर्ग को डराया कि उनके ग्रुप के सदस्य हर जगह हैं। अगर शोर किया तो उसे गोली मार दी जाएगी। लूट के बाद घर के अंदर खड़ी अपनी होंडा शाइन बाइक से फरार हो गए।

लूट की यह घटना चोरहटा थाना क्षेत्र के गोडहर मोहल्ले में एक सेवानिवृत कर्मचारी रमाशंकर सिंह तिवारी के घर में बुधवार शाम करीब 7.30 बजे की है। आरोपियों ने 10.30 बजे तक उसे बंधक बनाए रखा। गुरुवार को थाने में मामला दर्ज कराया गया। मौके पर एसपी और एडिशनल एसपी भी पहुंचे।

पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने बताया कि पीड़ित ने बताया 15 से 20 तोला सोना और तकरीबन 2 लाख कैश बदमाश ले गए हैं। घटना से पूर्व बदमाशों द्वारा घर की रैकी किए जाने का अनुमान है। पीड़ित ने बताया तीनों बदमाश पन्ना, सतना, कटनी और रीवा की मिली जुली भाषा का उपयोग कर रहे थे। अपराध पंजीबद्ध कर घटनास्थल में मिले हुए सबूतों के आधार पर विवेचना शुरू कर दी गई है। बुधवार को शाम 7.30 बजे आरोपियों ने बुजुर्ग के घर को गेट खटखटाया। जब नहीं खोला तो

उनसे यह कहा कि अंकल आपके बेटे राहुल का फोन नहीं लग रहा है। एक बार आप उससे बात करा दीजिए। बदमाशों के इरादों से अनजान सेवानिवृत कर्मचारी तीनों युवकों से बात करते-करते घर के अंदर आ गए। इसके बाद बदमाशों ने वृद्ध से पानी मांगा और जैसे ही सेवानिवृत कर्मचारी किचन से पानी लेकर लौटा तो तीन की संख्या में मौजूद बदमाशों में से एक ने पिस्तौल निकाल कर वृद्ध की कनपटी में रख दी और उसे बंधक बना लिया।

पिस्टल देखकर डरा बुजुर्ग: पीड़ित रामशंकर ने बताया कि जैसे ही मैंने पिस्टल देखी। उनके पैर पकड़ लिए। बोला कि तुम्हें जो चाहिए वह ले लो पर मुझे जान से मत मारो। मैं हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूं। मुझे हार्ट की भी बीमारी है। मैं घबरा गया पसीना पसीना हो गया। घबराहट की वजह से मेरा दम फूलने लगा, सांस लेते नहीं बन रहा था। मैंने बदमाशों को भरोसा दिलाया कि अगर वह मुझे जिंदा छोड़ देते हैं तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मैं लगातार भगवान की कसम खाता रहा। तब जाकर उन्होंने मुझे एक सोफे में बिठा दिया।

डकैतों ने बुजुर्ग को दवा खिलाई: पीड़ित बुजुर्ग ने बताया कि वह कुछ दिनों पूर्व ही कोल इंडिया की सर्विस से रिटायर्ड हुआ है। घटना के दिन उसका परिवार वृद्ध की गृहस्थी का सामान लेने महेंद्रगढ़ स्थित उसके किराए के आवास में गया था। रिटायर्ड कर्मचारी के बंधक बनाए जाने के दौरान ही पीड़ित की तबीयत भी बिगड़ी जिसपर बदमाशों ने उन्हें दवाई खिलाई। उसके बाद घर के हर कमरों में घुसकर रखी हुई अलमारी से लगभग 20 तोला सोना और तकरीबन 200000 कैश निकाल लिया।

एक दिन बाद बताया पूरा मामला: घटना के दिन बुजुर्ग डर गया था उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया। गुरुवार की सुबह पूरे मामले की जानकारी अपने पत्नी बेटे को दी। जिसके बाद सूचना मिलते ही तमाम रिश्तेदार पीड़ित के घर पहुंचे और मामले से पुलिस को बताया।

गुढ़ कांड के आरोपियों को सजा दिलाने में वाली टीम हुई पुरस्कृत

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। जिले के गुढ़ थाना अंतर्गत भैरव बाबा मंदिर के समीप हुए गैंग रेप के मामले में सभी आरोपियों को ता उम्र की सजा होने के बाद, पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने आरोपियों को सजा दिलाने में लगी पूरी टीम को पुरस्कृत किया। एसपी विवेक सिंह ने बताया कि बीते 21 अक्टूबर 2024 को गुढ़ थाना अंतर्गत भैरव बाबा मंदिर के समीप नव दंपति घूमने गए हुए थे, जहां उनके साथ आरोपियों ने गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया था। घटना के बाद पुलिस की अलग-अलग टीम बनाकर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। एसपी ने बताया कि वारदात में पांच आरोपियों ने गैंग रेप की घटना की थी, जबकि तीन लोगों ने उनका सहयोग किया था। पुलिस ने मामले में सभी आठों आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया था और बहुत कम समय में इन सभी आरोपियों को ता उम्र की सजा भी हो गई है। इस पूरे मामले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी अधिकारी और कर्मचारियों सहित पैरवी करने वाले अधिवक्ता को आज पुरस्कृत किया गया है।

दुधारू गायों के पंजीयन की अंतिम तिथि आज

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा प्रदेश की मूल गोवंशीय नस्ल एवं भारतीय उन्नत नस्ल की दुधारू गायों को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं डॉ राजेश मिश्रा ने बताया कि जिन पशुपालकों के पास भारतीय नस्ल की गिरि, साहीवाल, थारपारकर एवं हरियाणा आदि नस्ल की गाय हों तथा उनका दुग्ध उत्पादन प्रति दिवस 6 लीटर से अधिक हो वह अपने पशु का पंजीयन चार अप्रैल तक विकासखण्ड स्तर अथवा निकटतम पशु चिकित्सालय में करा सकते हैं। अधिकतम दुग्ध उत्पादन वाले प्रथम 10 गौवंशों का सुबह-शाम एवं दूसरे दिन कुल तीन समय दुग्ध क्षमता का आकलन विभाग के अधिकारियों द्वारा पशु मालिक के घर जाकर सूचीबद्ध किया जाएगा। इस प्रकार जिले के प्रत्येक विकासखण्ड से प्राप्त सूची में से अधिकतम दूध उत्पादन वाले प्रथम तीन गौवंश के पशुपालकों के नाम राज्य स्तर पर प्रेषित किए जाएंगे।

समर्थन मूल्य पर गेंहू खरीदी के लिए पंजीयन की तिथि बढ़ी

अब 9 अप्रैल तक होगा पंजीयन

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य देने के लिए शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीद की जाती है। समर्थन मूल्य पर गेंहू खरीदी के लिए किसानों के पंजीयन की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 9 अप्रैल कर दिया गया है। किसान अब समर्थन मूल्य पर गेंहू खरीदी के लिए 9 अप्रैल तक पंजीयन करा सकते हैं। किसान एमपी किसान एप, ई-उपार्जन पोर्टल तथा ई-उपार्जन मोबाइल एप पर अपना पंजीयन करा सकते हैं। शासन द्वारा वर्तमान वर्ष के लिए गेंहू का समर्थन मूल्य 2425 रूपये तथा सरकार द्वारा घोषित 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस के साथ किसानों से 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेंहू का उपार्जन होगा।

इस संबंध में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि रीवा जिले में गेंहू उपार्जन के लिए खरीदी केन्द्र निर्धारित कर दिए गए हैं। किसान इन खरीदी केन्द्रों में गेंहू उपार्जन के लिए पंजीयन करा सकते हैं। सभी किसान निर्धारित खरीदी केन्द्रों में अपना आनलाइन पंजीयन अवश्य करायें। पंजीकृत किसानों से ही समर्थन मूल्य पर गेंहू की खरीद की जायेगी। स्वयं के मोबाइल, कम्प्यूटर, खरीदी केन्द्र तथा ग्राम पंचायत कार्यालय में स्थापित सुविधा केन्द्र में पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। किसान 50 रुपए का शुल्क देकर एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केन्द्र तथा साइबर कैफे में पंजीयन करा सकते हैं। कलेक्टर ने बताया कि पंजीयन के समय किसान आधार संख्या से लिंक बैंक खाते दर्ज करें जिससे ऑनलाइन भुगतान किया जा सके। पंजीयन कराने के लिए किसान को बोये गये खेत के खसरा नंबर की ऋण पुस्तिका, आधार से लिंक बैंक खाते की जानकारी देकर अपना पंजीयन करा सकते हैं। बटाईदार एवं सिकमी किसानों के लिए भी ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था की गयी है। केवल पंजीकृत किसानों को ही गेंहू उपार्जन का लाभ दिया जायेगा।

नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन

रीवा . चिरहुला मंदिर प्रांगड़ में विप्र सेवा संघ द्वारा नव निर्मित धर्मशाला के शुभारंभ के अवसर पर श्रीमद भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। इसके साथ ही संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव शुक्ला द्वारा 30 मार्च से 6 अप्रैल तक लगातार बृहद निशुल्क मैडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। जहां पर किडनी, हार्ट, लिबर, स्किन, नेत्ररोग, गायनी, दांतो व अन्य गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु देश के बरिष्ठ चिकित्सको द्वारा निशुल्क सेवाएं दी रही हैं। विप्र सेवा संघ द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि श्रीरामनवमी पर 6 अप्रैल को देश के वरिष्ठ चिकित्सकों का सम्मान समारोह किया जायेगा।

आकस्मिकता योजनान्तर्गत एक करोड़ रूपये से अधिक की राशि स्वीकृत

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। जिला राहत समिति की अनुशंसा पर आकस्मिकता योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के अत्याचार पीड़ित 162 व्यक्तियों को एक करोड़ 12 लाख दस हजार 500 सौ की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। जिला संयोजक अनुसूचित जाति एवं जनजातीय कार्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अनुसूचित जाति के 104 हितग्राहियों को 70 लाख पच्चीस हजार रूपये तथा अनुसूचित जनजाति के 50 हितग्राहियों व्यक्तियों को 43 लाख 87 हजार 500 रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

स्वत्वाधिकारी मुद्रक/प्रकाशक संदीप द्विवेदी द्वारा मीडिया ऑडीटर पब्लिकेशन प्रा.लिमि. राजीव मार्ग निराला नगर रीवा से मुद्रित कर मीडिया ऑडीटर कार्यालय राजीव मार्ग निराला नगर रीवा से प्रकाशित, **संपादक संदीप द्विवेदी**, आर.एन.आई नं. 69082/97, डाक पंजीयन क्र.- म. प्र./ रीवा संभाग/ 46/2023-2025, प्रधान कार्यालय रीवा (सिटी कार्यालय चक्रधर सिटी सेंटर रीवा) फोन. नं. 9589645803, 7974467831 Mediaauditor1@gmail.com सभी विवादों का न्याय क्षेत्र रीवा होगा।